धनबाद, रविवार
05 जुलाई 2026
वर्ष : 03 अंक : 275
पृष्ठ : 08
मूल्य: 3 /-
E-Mail:-truthpath941@gmail.com

हिन्दी दैनिक समाचार

ट्रूथ पथ

ब्रीफ न्यूज

केंद्र सरकार ने 17 पाकिस्तानियों समेत 23 और दहशतगर्दों को घोषित किया आतंकवादी

नई दिल्ली, (एजेंसी) : आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत गृह मंत्रालय ने 23 और दहशतगर्दों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम-1967 (यूएपीए) के तहत आतंकवादी घोषित किया है। इस कार्रवाई के बाद यूएपीए की चौथी अनुसूची में नामित आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। घोषित 23 आतंकवादियों में 17 पाकिस्तानी और छह भारतीय नागरिक हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा कि इन आतंकवादियों को औपचारिक रूप से नामित किए जाने से उनके वित्तीय नेटवर्क, आवाजाही, भर्ती क्षमता और आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 23 खूंखार आतंकवादियों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है।

चंपत राय के बचाव में उतरे अयोध्या के संत, ट्रस्ट से इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की अपील

अयोध्या, (एजेंसी) : श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (ट्रस्ट) के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर चल रही चचाओं के बीच अयोध्या संत मंडल उनके समर्थन में उतर आया है। संतों ने ट्रस्ट से चम्पत राय का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की अपील की है।

ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ट्रस्ट की छह जुलाई को अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें उनके इस्तीफे पर विचार हो सकता है।बैठक से पहले संतों ने चंपत राय का समर्थन करते हुए उनका बचाव किया है। शनिवार को अयोध्या संत मंडल की एक बैठक हुई जिसके बाद संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संतों ने कहा कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट आने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने की अपील की।

ऊर्जा संकट में दुनिया ने देखा भारत की कूटनीति का जलवा: पीएम मोदी

जयपुर,(एजेंसी) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट का जिक्र कर कहा कि इस संकट के समय भारत की कूटनीतिक शक्ति का जलवा दुनिया को दिखा, इस शक्ति ने देश को चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने में मदद की।

पीएम मोदी ने बताया कि पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष ने 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट पैदा किया था। इस चुनौती के बावजूद, भारत ने सही फैसलों, सटीक आकलन, प्रभावी रणनीति और कूटनीतिक शक्ति का सकारात्मक इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक स्थिति संभाली। उन्होंने कहा कि संकट से पहले भारत 25-26 देशों से ईंधन आयात करता था, लेकिन युद्ध के दौरान भारत की कूटनीति के कारण यह संख्या 40 से अधिक देशों तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस अवधि में भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि उसके लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, उन पर ईंधन संकट के बीच अफवाहें फैलाने और राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गलत इरादे वाले सफल नहीं हुए और देश में दूर-दराज के इलाकों में भी छोटी-मोटी अड़चनों के अलावा ईंधन आपूर्ति में कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। पीएम मोदी ने कहा कि जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थीं, तब पर्दे के पीछे किस स्तर पर दिन-रात काम हो रहा था और स्थिति को संभाला जा रहा था, यह कभी न कभी इतिहास में लिखा जाएगा। अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहकर अफवाहों, डर और भ्रम फैलाने वालों की साजिशों को नाकाम किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों के इसी विश्वास के भरोसे देश आगे बढ़ रहा है।पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकारें परियोजनाओं का शिलान्यास करके उन्हें अधूरा नहीं छोड़तीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए दिन-रात काम करती हैं। उन्होंने दो महीने पहले रिफाइनरी में हुए हादसे के बाद भी इतनी तेजी से काम पूरा करने की सराहना की, यह दिखाता हैं कि नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो। पीएम मोदी ने देश की दृढ़ शक्ति को रेखांकित कर कहा कि इस कारण सबसे बड़ा संकट भी छोटा हो गया और भारत ने अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर जोर देकर कांग्रेस सरकारों पर राजस्थान के जल संकट को दूर करने में ठोस काम न करने का आरोप लगाया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान को बिना किसी विवाद के नर्मदा का पानी साझा करने का उदाहरण दिया, यह दशार्ते हुए कि भाजपा क्षेत्रवाद और बंटवारे की राजनीति नहीं करती।

रक्षा राज्य मंत्री सेठ 14 किमी की पैदल यात्रा कर पहुंचे अमरनाथ, की पूजा अर्चना

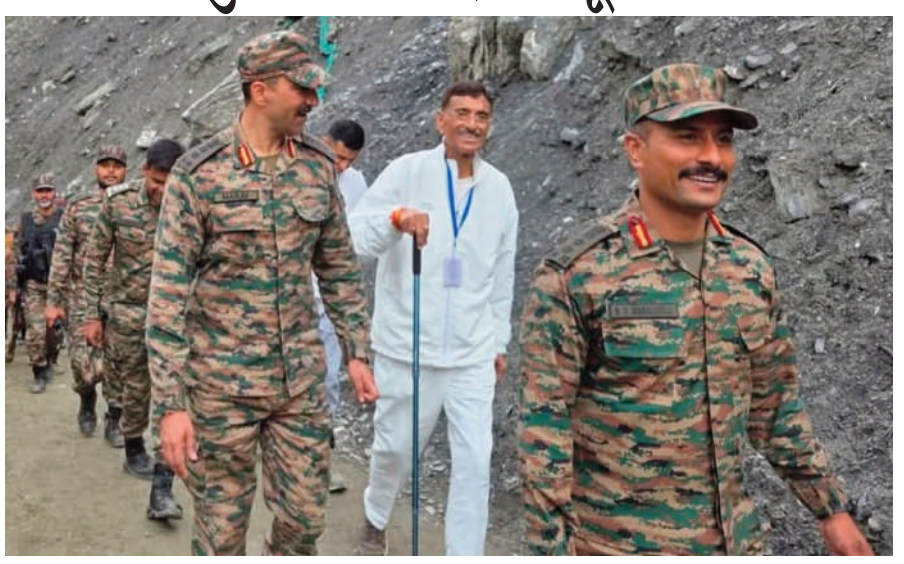

रांची, (एजेंसी) : केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा में सहभागिता करते हुए बालटाल बेस कैंप से लगभग 14.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा बफानी की पवित्र गुफा में पहुंचकर विधिवत दर्शन एवं पूजा-अर्चना की। उन्होंने बाबा अमरनाथ से देशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

यात्रा के दौरान सेठ ने श्रद्धालुओं के लिए की गई सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, यातायात तथा अन्य व्यवस्थाओं का भी विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों एवं चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच भारतीय सेना, सशस्त्र बलों, जम्मू-कश्मीर पुलिस, प्रशासन तथा विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा के लिए किए जा रहे कार्यों की मुक्तकंठ से सराहना की।सेठ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भारतीय सेना और सुरक्षा बल जिस समर्पण, अनुशासन एवं सेवा-भाव से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, वह राष्ट्रसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठन निस्वार्थ भाव से श्रद्धालुओं की सेवा कर भारतीय संस्कृति की सेवा-परंपरा को सशक्त बना रहे हैं।उन्होंने पवित्र अमरनाथ यात्रा के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधाओं की उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे लाखों श्रद्धालु सुरक्षित एवं सुगमता के साथ बाबा बफानी के दर्शन कर पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बाबा अमरनाथ की पावन यात्रा उनके जीवन की एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभूति रही। उन्होंने कहा कि बाबा बफानी का आशीर्वाद समस्त देशवासियों पर बना रहे तथा भारत निरंतर शांति, समृद्धि, विकास और वैभव के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

रांची के निजी अस्पताल में युवक की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

रांची, 04 जुलाई (हि.स.)। राजधानी रांची के निजी राज अस्पताल में इलाज के दौरान 18 वर्षीय युवक की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर चिकित्सकीय लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पैर के फ्रैक्चर के इलाज के लिए भर्ती कराए गए युवक की उपचार में लापरवाही के कारण मौत हुई। साथ ही, मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा 22 लाख रुपये का बिल थमाए जाने के आरोप ने मामले को और तूल दे दिया है। घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।दरअसल, लातेहार जिले के निवासी 18 वर्षीय राजू कुमार रंजन 24 मई को सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। दुर्घटना में उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके इलाज के लिए उन्हें रांची स्थित राज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने आवश्यक चिकित्सकीय सावधानियां नहीं बरतीं। उनका कहना है कि दो से तीन दिनों तक घाव की नियमित ड्रेसिंग नहीं की गई, जिससे संक्रमण तेजी से फैल गया और उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई।परिजनों के अनुसार, संक्रमण गंभीर होने के बाद राजू को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उनका आरोप है कि यदि समय पर समुचित इलाज और देखभाल की जाती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। परिजनों ने यह भी सवाल उठाया कि जब चोट केवल पैर में थी, तो संक्रमण इतना गंभीर कैसे हो गया कि मरीज की मृत्यु हो गई।

मृत्यु के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा 22 लाख रुपये का बिल जमा करने के लिए कहे जाने से परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों के आग्रह पर राजू के शव का पोस्टमार्टम राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में कराया गया।मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर संज्ञान लेते हुए रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को पूरे प्रकरण की गहन एवं निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सिविल सर्जन को जांच का दायित्व सौंपते हुए पूरे मामले की जांच के लिए जिला स्तरीय विशेष जांच टीम का गठन किया है।

राज्यपाल ने श्री हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चना, श्री राम वाटिका सामुदायिक हॉल का किया उद्घाटन

रांची, (एजेंसी) :झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शनिवार को रांची के महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। पूजा-अर्चना के बाद राज्यपाल ने मंदिर परिसर में नवनिर्मित वातानुकूलित सामुदायिक हॉल श्री राम वाटिका का उद्घाटन भी किया।उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सेवा-भाव, सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कारों के संवर्धन के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि श्री राम वाटिका धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ-साथ जनसेवा के विविध कार्यों का एक प्रेरणादायी केंद्र बनेगी।

राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री हनुमान मंदिर वर्षों से जन-आस्था, सेवा और सामाजिक समरसता का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां धार्मिक आयोजनों के अलावा समाजहित के अनेक कार्य लगातार संचालित होते रहे हैं। राज्यपाल ने इस जनोपयोगी सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए श्री हनुमान मंदिर समिति, पंजाबी हिंदू बिरादरी तथा सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान श्रीराम और प्रभु हनुमान का जीवन सेवा, समर्पण, विनम्रता और कर्तव्यनिष्ठा का आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि शक्ति तभी सार्थक है, जब उसमें विनम्रता हो, ज्ञान तभी श्रेष्ठ है, जब उसमें सेवा का भाव हो और जीवन तभी सफल माना जाता है, जब वह लोकमंगल के लिए समर्पित हो।

राज्यपाल ने गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्तियों ह्न परहित सरिस धरम नहि भाई, पर पीड़ा सम नहि अधमाईह्व का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में परोपकार और सेवा को सर्वोच्च धर्म का स्थान दिया गया है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश अपनी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे धार्मिक और सामाजिक केंद्र समाज में सेवा, सहयोग, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।राज्यपाल ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने जीवन में सेवा, अनुशासन और संस्कारों को प्राथमिकता दें तथा समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि यदि युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहेगी, तो समाज और राष्ट्र दोनों अधिक सशक्त, जागरूक और संस्कारित बनेंगे।अपने संबोधन के अंत में राज्यपाल ने सभी श्रद्धालुओं से प्रेम, सद्भाव, सहयोग और सेवा की भावना को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि यही भगवान श्रीराम और प्रभु हनुमान के जीवन का वास्तविक संदेश है।

नबाद में प्रिंस खान पर बुलडोजर एक्शन, धमकी की राजनीति गरमः सांसद ढुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी के बीच आरोपों की जंग तेज

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबादः धनबाद में अपराध, राजनीति और पुलिस कार्रवाई एक बार फिर आमने-सामने दिखाई दे रही है। एक ओर भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ धनबाद पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए वासेपुर स्थित कमर मकदूमी में उसके घर पर बुलडोजर चला दिया, तो दूसरी ओर इसी मामले को लेकर धनबाद की राजनीति भी पूरी तरह गरमा गई है।शनिवार को धनबाद सांसद ढुलू महतो ने दावा किया कि उन्हें भी कई बार प्रिंस खान की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है और इसकी शिकायत उन्होंने धनबाद एसएसपी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक को दी है। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद ढुलू महतो और प्रिंस खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए दोनों के बीच कथित संबंधों और रंगदारी नेटवर्क की जांच की मांग की है।इधर पुलिस का कहना है कि प्रिंस खान के घर पर की गई कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेश के तहत हुई है। हालांकि सांसद और विधायक द्वारा

एक-दूसरे पर लगाए गए आरोप उनके अपने-अपने दावे हैं, जो अब पुलिस जांच के दायरे में है।शनिवार सुबह धनबाद के वासेपुर इलाके में भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर चला। एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में डीएसपी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रकाश सोय, सीसीआर डीएसपी ऋत्विक श्रीवास्तव सहित तीन डीएसपी और छह थानों की पुलिस बल तैनात रहा। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए।कार्रवाई के दौरान मीडिया को सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कुछ दूरी पर रखा गया। पूरे अभियान की वीडियोग्राफी कराई गई और बुलडोजर से मकान को पूरी तरह ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई।कार्रवाई के बाद डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि न्यायालय द्वारा प्रिंस खान के घर की कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया गया था, जिसका शनिवार को तामिला कराया गया। उन्होंने कहा कि लगातार कुर्की-जब्ती की कार्रवाई के कारण भवन काफी जर्जर हो चुका था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उसे बुलडोजर से गिराया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय के आदेश के अनुरूप की गई है।बताया जा रहा है कि हाल ही में निरसा विधायक अरूप चटर्जी को कथित धमकी मिलने के बाद पुलिस ने प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी है, हालांकि पुलिस इसे नियमित कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बता रही है।उधर, सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में धनबाद सांसद ढुलू महतो ने कहा कि वह भी गैंगस्टर प्रिंस खान के निशाने पर हैं। सांसद ने दावा किया कि एक जुलाई को भी उन्हें धमकी मिली थी और इससे पहले भी कई बार फोन कॉल के जरिए धमकियां दी गई हैं।

उन्होंने बताया कि दिल्ली जाने के दौरान उन्हें फोन पर धमकी मिली थी और शुक्रवार शाम भी एक विदेशी नंबर से कॉल आया। सांसद ने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने पहले ही धनबाद एसएसपी, पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री को लिखित रूप से दे दी है।ढुलू महतो ने कहा कि वह चाहते हैं कि प्रिंस खान को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। उन्होंने कहा कि जब सांसद और विधायक तक सुरक्षित नहीं हैं तो राज्य सरकार को अपराधियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि राज्य सरकार प्रभावी कार्रवाई करेगी तो केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग करेगी और अपराधी को कहीं से भी गिरफ्तार कर भारत लाया जाएगा।उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि धनबाद में अपराध नहीं बल्कि एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, पुल-पुलिया और विकास कार्यों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने गयापुल-मटकुरिया, गोविंदपुर और निरसा फ्लाईओवर का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास कार्यों का श्रेय लेने वाले पहले अपना योगदान भी बताएं। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।सांसद की प्रेस वार्ता के कुछ ही समय बाद निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद ढुलू महतो और गैंगस्टर प्रिंस खान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने निरसा थाना में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।अरूप चटर्जी ने दावा किया कि दो दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद ढुलू महतो के कथित अवैध कारोबार और गैंगस्टर प्रिंस खान से कथित संबंधों की जांच की मांग की थी। उनका आरोप है कि इस सवाल का जवाब देने के बजाय उन्हें प्रिंस खान के जरिए धमकी दिलाई गई।विधायक ने आरोप लगाया कि दर्ज कराई गई एफआईआर में उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रिंस खान कथित तौर पर ढुलू महतो के इशारे पर धनबाद में लोगों को धमकी देकर रंगदारी वसूलता है और उनकी कथित अवैध संपत्तियों का संरक्षण करता है।उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम रांची विधानसभा में रहने के दौरान उन्हें प्रिंस खान की ओर से धमकी भरा मैसेज मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने तत्काल धनबाद एसएसपी और मीडिया को दी तथा बाद में एफआईआर दर्ज कराई।अरूप चटर्जी ने सांसद के दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ढुलू महतो को एक जुलाई को धमकी मिली थी तो उन्होंने इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से अब क्यों दी। विधायक ने कहा कि या तो सांसद को मिला धमकी का संदेश फर्जी है या फिर दोनों के बीच संबंधों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में उनकी ही सरकार है, ऐसे में यदि उन्हें धमकी मिली थी तो तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

विधायक ने दावा किया कि प्रिंस खान भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठकर अपने नेटवर्क का संचालन कर रहा है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी इंटरपोल जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से ही संभव होगी। उन्होंने मांग की कि प्रिंस खान के पूरे नेटवर्क और उसके कथित संरक्षकों की भी जांच हो।अरूप चटर्जी ने यह भी कहा कि यदि उनके साथ भविष्य में कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए सांसद ढुल्लू महतो और प्रिंस खान जिम्मेदार होंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद में ढुल्लू महतो भाई की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि मुंबई की तर्ज पर धनबाद में भी ढुल्लू भाई बनने की कोशिश हो रही है।फिलहाल धनबाद में भसगौड़ा अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ न्यायालय के आदेश पर उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है, तो दूसरी ओर सांसद और विधायक के बीच गंभीर आरोप-प्रत्यारोप ने इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप दे दिया है।अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है कि धमकी के इन मामलों, दर्ज एफआईआर और लगाए गए आरोपों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर प्रिंस खान और उसके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

संक्षिप्त खबरें

पोड़ैयाहाट बाजार में चला प्रशासन का बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

गोड्डा : पोड़ैयाहाट मुख्य मार्ग पर लग रहे जाम और पैदल चलने में हो रही परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार को पोड़ैयाहाट बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सीओ अमित किस्कू के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने बाजार के दोनों ओर सड़क किनारे लगाए गए ठेले, टेंट और अस्थायी दुकानों को बुलडोजर की मदद से हटाया।सुबह 10 बजे से शुरू हुई कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई से पहले माइक से लोगों को चेतावनी दी गई थी और स्वयं सामान हटाने का समय दिया गया। इसके बावजूद नहीं मानने वाले दुकानदारों के अतिक्रमण को जेसीबी से तोड़ा गया। सीओ अमित किस्कू मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी की।प्रशासन का कहना है कि बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम लग रहा था। स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस को भी परेशानी होती थी। कई बार दुर्घटना की स्थिति भी बन जाती थी। बार-बार समझाने के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटा तो मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी।

इस दौरान लगभग 50 मीटर तक फैले अवैध निर्माण, सीढ़ी, टिन शेड और ठेले हटाए गए। दुकानदारों से अपील की गई कि वे सरकारी जमीन पर कब्जा न करें और निर्धारित जगह पर ही दुकान लगाएं।स्थानीय लोगों ने अभियान का स्वागत किया। ग्रामीणों ने कहा कि अतिक्रमण हटने से बाजार में आवागमन सुगम होगा।सीओ अमित किस्कू ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सरकारी जमीन को मुक्त कराकर आम जनता के लिए रास्ता साफ रखा जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तय है।

रांची के पिठोरिया क्षेत्र में डाक विभाग की बड़ी लापरवाही: डाकिया के घर से मिले एक साल से अटके आधार, पैन, एटीएम कार्ड और सरकारी नोटिस

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : रांची के कांके प्रखंड स्थित पिठोरिया डाकघर से डाक विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। पिछले करीब एक वर्ष से क्षेत्र के सैकड़ों लोगों तक उनकी महत्वपूर्ण डाक नहीं पहुंच रही थी। लगातार शिकायतों और ग्रामीणों के विरोध के बाद हुई जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया।जांच के दौरान डाक विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने संबंधित डाकिया के घर की तलाशी ली। वहां से कई बोरों में भरी बड़ी संख्या में लंबित डाक बरामद हुई। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक के साथ-साथ लोक अदालत, कोर्ट से निर्गत पत्र और आयकर विभाग के महत्वपूर्ण नोटिस भी शामिल थे, जो महीनों से लोगों तक नहीं पहुंच पाए थे।ग्रामीणों का कहना है कि समय पर दस्तावेज नहीं मिलने से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंकिंग कार्य कराने, अदालती आदेशों और कानूनी मामलों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को महत्वपूर्ण नोटिस समय पर नहीं मिलने से आर्थिक और मानसिक पीड़ा भी झेलना पड़ी।मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित डाकिया विकास कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और यदि किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।डाक विभाग ने लंबित डाक के शीघ्र वितरण के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। इसके तहत सभी अटकी हुई डाक को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाया जाएगा।इस घटना ने डाक विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि केवल निलंबन से उनकी भरपाई नहीं होगी। अब सभी की नजर इस बात पर है कि विभाग दोषियों पर क्या कार्रवाई करता है और प्रभावित लोगों को उनके जरूरी दस्तावेज कितनी जल्दी उपलब्ध कराता है।

गौशाला में शुरू हुआ एफएमडी टीकाकरण अभियान बरसात में पशुओं को संक्रमण से बचाने पर जोर

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

कोडरमा : केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शनिवार को श्री कोडरमा गौशाला परिसर में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी) टीकाकरण अभियान की शुरूआत की गई।इस अवसर पर कोडरमा प्रखंड की पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. निर्मला मिंज अपनी टीम के साथ गौशाला पहुंचीं और गौशाला समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के सहयोग से पशुओं को एफएमडी का टीका लगाया।डॉ. निर्मला मिंज ने बताया कि एफएमडी पशुओं में होने वाला एक संक्रामक वायरल रोग है जिससे बचाव के लिए समय पर टीकाकरण बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में संक्रमण फैलने की आशंका अधिक रहती है। इस बीमारी के कारण पशुओं के पैरों में सूजन, मुंह और जीभ पर छाले पड़ना, जीभ का मोटा होना तथा चारा खाने में कठिनाई जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।इससे पशुओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन और पशुपालकों की आय भी प्रभावित होती है।उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा यह अभियान पूरे कोडरमा जिले में चलाया जा रहा है।शहर के सभी वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के घर-घर जाकर पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। जिन पशुपालकों के पशुओं का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है वे निकटतम प्रखंड पशु चिकित्सालय से संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने सभी पशुपालकों से समय पर टीकाकरण कराकर अपने पशुओं को एफएमडी जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने की अपील की। मौके पर गौशाला समिति के कार्यकारी सचिव अरुण मोदी, प्रबंधक अनंत चंद्रा, पशुधन सहायक रजनीश कुमार, गौशाला कर्मी सौरभ मिश्रा, विष्णु कुमार आदि मौजूद थे।

प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य परीक्षा के कंप्यूटर, एआइ व साइबर सिक्यूरिटी का परीक्षाफल जारी, 98 सफल

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : हाइस्कूलों में पहली बार कंप्यूटर साइंस, एआइ व कोडिंग तथा साइबर सिक्यूरिटी व डेटा साइंस विषय के शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है।इससे संबंधित शनिवार को झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाझ2025 के तहत कंप्यूटर साइंस, एआइ व कोडिंग तथा साइबर सिक्यूरिटी विषय में 98 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल जारी किया गया।इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के परीक्षा नियंत्रक ने आयोग की वेबसाइट पर आवश्यक सूचना जारी की है।वेबसाइट पर अभ्यर्थियों का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है.

प्रशासन के निर्देश बेअसर, फायर एनओसी को लेकर उलझे कोचिंग व हॉस्टल संचालक,पूरे भवन का एक साथ बनेगा फायर एनओसी, बीएसएल के पुराने भवनों की बनावट बनी बड़ी बाधा

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

बोकारो : लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन ने बोकारो टाउनशिप में कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, होटल और अन्य व्यावसायिक संस्थानों की अग्नि सुरक्षा जांच के निर्देश दिए थे।सभी संस्थानों को फायर एनओसी लेकर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया था।इसके बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। फायर विभाग के अनुसार अब तक किसी भी संस्थान की ओर से फायर एनओसी के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।पिछले जून माह में डीसी बोकारो अजय नाथ झा के निर्देश पर मजिस्ट्रेट सत्यबाला सिन्हा की निगरानी में अग्निशमन विभाग की टीम ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर बिना फायर एनओसी संचालित हो रहे संस्थानों को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी संचालकों ने पहल नहीं की है।पिछले जून माह में सेक्टर-04 सिटी सेंटर स्थित प्लॉट संख्या एचबी-04 की एक बहुमंजिला बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गयी थी। आग मुख्य बिजली मीटर से शुरू होकर तारों के माध्यम से तेजी से फैल गयी थी। सीढ़ियों में धुआं भर जाने से ऊपरी मंजिल पर संचालित कोचिंग संस्थान में अफरा-तफरी मच गयी थी। छात्र-छात्राएं, शिक्षक और कर्मचारी छत के रास्ते पास के भवन की दीवार पार कर सुरक्षित बाहर निकले थे। नीचे संचालित पार्लर में मौजूद लोगों को भी समय रहते बाहर निकाल लिया गया था। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था।इस घटना में मुख्य बिजली मीटर, विद्युत पैनल, एमसीबी, वायरिंग सहित करीब 25 हजार रुपये की संपत्ति जलकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। समय रहते लोगों के बाहर निकल जाने से बड़ा हादसा टल गया था।एक कोचिंग संचालक अमित कुमार ने बताया कि उनका संस्थान किसी व्यावसायिक भवन के केवल एक कमरे में संचालित होता है। उन्होंने फायर

एनओसी के लिए जानकारी ली, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी एक कमरे या एक संस्थान के लिए अलग से फायर एनओसी जारी नहीं हो सकती। पूरे भवन का एक साथ फायर एनओसी बनना आवश्यक है। ऐसे में भवन मालिक की पहल के बिना किरायेदार संचालक एनओसी नहीं बनवा पा रहे हैं।एक हॉस्टल संचालक सतीश कुमार ने बताया कि उनका भवन बीएसएल के स्वीकृत नक्शे के अनुसार बना है।भवन में प्रवेश और निकास का केवल एक ही रास्ता है। वर्तमान फायर सुरक्षा मानकों के अनुसार अलग आपातकालीन निकास आवश्यक माना जा रहा है। पुराने भवन में दूसरा निकास बनाना आसान नहीं है।ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि फायर एनओसी कैसे प्राप्त करें।बोकारो के जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्रीभगवान ओझा ने बताया कि अग्नि सुरक्षा का मूल्यांकन पूरे भवन के आधार पर किया जाता है। भवन में आपातकालीन निकास, सीढ़ियां, अग्निशमन यंत्र, जल आपूर्ति, विद्युत सुरक्षा सहित अन्य मानकों की जांच के बाद ही फायर एनओसी जारी की जाती है। यदि भवन निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो आवश्यक सुधार के बाद ही एनओसी मिल सकती है।किसी एक कमरे या एक संस्थान के लिए अलग से फायर एनओसी देने का प्रावधान नहीं है।कोचिंग और हॉस्टल संचालकों का कहना है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन बीएसएल के पुराने नक्शे पर बने भवनों और किरायेदारी व्यवस्था के कारण कई व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही हैं।उनका कहना है कि भवन मालिक की सहमति के बिना वे एनओसी की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते।संचालकों ने प्रशासन से मांग की है कि पुराने भवनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और व्यवहारिक समाधान तय किया जाए, ताकि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन भी हो और संस्थानों के संचालन में अनावश्यक बाधा भी न आए।

आजसू के राज्यस्तरीय महिला अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित,महिलाओं की राजनीति-सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करना लक्ष्य है : सुदेश महतो

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि झारखंड में महिलाओं की राजनीतिकझसामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करवाना पार्टी का लक्ष्य है। इसके लिए पार्टी में प्रदेश से बूथ स्तर तक महिला नेतृत्व खड़ा करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि आजसू ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी पहल करते हुए पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। लेकिन हेमंत सरकार महिला विरोधी है। श्री महतो ने शनिवार को खेलगांव स्थित टाना भगत इनडोर स्टेडियम में पार्टी के सहयोगी संगठन अखिल झारखंड महिला संघ के राज्यस्तरीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। अधिवेशन में राज्य के सभी पंचायतों से हजारों महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्यस्तरीय अधिवेशन सशक्त महिला, समृद्ध महिला, स्वावलंबी महिला के संकल्प के साथ संपन्न हुआ।सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार महिलाओं को छलने का काम कर रही है। राज्य में महिला सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मईया सम्मान के नाम पर चुनावी राजनीति की गई, लेकिन दो वर्ष में 18 वर्ष की हो चुकी महिलाओं का नाम सूची में नहीं जोड़ा जा रहा। राज्य सरकार विगत दो वर्ष में 18 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं का नाम

जोड़कर उन्हें 60,000 रुपया भुगतान करे, अन्यथा महिलाएं सड़क पर उतरेंगी।श्री महतो ने कहा कि महिला शक्ति को नजरअंदाज कर समाज, राज्य और देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, अपराध और बिचौलियों की व्यवस्था के कारण महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पर लगातार प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं।सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि हेमंत सरकार महिलाओं के प्रति दोहरा मापदंड अपना रही है। उन्होंने कहा कि आजसू ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, संजीवनी और जेएसएलपीएस जैसे माध्यमों को सशक्त किया गया। साथ ही सुदेश महतो के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर उन्हें सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की गई।विधायक निर्मल महतो ने कहा कि कहा कि आज महिलाएँ घूँघट और चौखट से बाहर निकलकर नेतृत्व की नई पहचान बना रही हैं। इसी सोच के अनुरूप संगठन में महिलाओं की संगठन में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिसका सशक्त उदाहरण आज का यह राज्य स्तरीय अधिवेशन है।अधिवेशन को गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, मांडू विधायक निर्मल महतो, पूर्व मंत्री रामचंद्र सिहस, पूर्व विधायक डॉ लम्बोदर महतो, पूर्व विधायक सुनीता चौधरी, केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत, नेहा महतो, वायलेट कच्छप, पार्वती देवी, संजय मेहता, शोभा पॉल, परमेश्वरी शांडिल्य, प्रीति दीवान, सहानी एक्का आदि ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता रांची जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत ने की।इस अधिवेशन में महिला सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक भागीदारी, महिला सुरक्षा, स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण तथा संगठन के भावी कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।

राजकीय श्रावणी मेला: देवघर में इंटर स्टेट को-ऑर्डिनेशन की बैठक, झारखंड-बिहार के आला अधिकारी जुटे -टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और समन्वय के दम पर बदलेगा मेला प्रबंधन का स्वरूप

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

देवघर : राजकीय श्रावणी मेला के सफल, सुरक्षित और सुगम संचालन को लेकर शनिवार को देवघर सर्किट हाउस में बिहार और झारखंड के अधिकारियों की महत्वपूर्ण इंटर स्टेट को-ऑर्डिनेशन बैठक हुई।संताल परगना आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दोनों राज्यों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात, आपदा प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर साझा रणनीति तय की।बैठक में संताल परगना आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि सुल्तानगंज से देवघर और बासुकीनाथ तक कांवरिया पथ पर पड़ने वाले सभी जिलों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जिलों में समान रूप से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी। उन्होंने बताया कि इस बार सूचना प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए व्हाट्सएप आधारित नेटवर्क तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया जायेगा, जिससे किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई संभव हो सके।देवघर डीसी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहने की संभावना को देखते हुए व्यापक प्रबंध किये गये हैं।भीड़ नियंत्रण के लिए विभिन्न स्थानों पर होल्डिंग प्वाइंट और टेंट सिटी बनाये गये हैं, जहां बिजली, पंखा, पेयजल, शौचालय, स्नानागार, मोबाइल चार्जिंग और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मेले में वीआइपी अथवा आउट ऑफ टर्न दर्शन की सुविधा नहीं रहेगी।बैठक में निर्णय लिया गया कि डबल डेकर कांवरिया वाहनों के देवघर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।साथ ही बिहार से आने वाले वाहनों की छतों पर श्रद्धालुओं को बैठाकर लाने पर भी सख्ती बरती जायेगी।इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सीमावर्ती जिलों से सहयोग मांगा गया है।भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने कहा कि भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, देवघर, दुमका और गोड्डा प्रशासन के बीच लगातार सूचना साझा की जायेगी। अंतरराज्यीय सीमा के थानों को विशेष रूप से सक्रिय रखते हुए गश्ती और चेकिंग अभियान चलाया जायेगा। दोनों राज्यों के अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी पूरे मेले के दौरान चौबीसों घंटे संपर्क में रहेंगे।बैठक की शुरूआत में एसडीओ, देवघर रवि कुमार ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से श्रावणी मेला की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। वहीं डीसी दुमका ने बासुकीनाथ मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी साझा की।

पशुतस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़: कंटेनर से 42 मवेशी बरामद, यूपी व गढ़वा के तीन तस्कर गिरफ्तार

पलामू : जिले के नावाबाजार थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार तड़के एनएच 98 पर छापेमारी कर अवैध रूप से ले जाये जा रहे 42 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है।इस मामले में मौके से तीन अंतरराज्यीय पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, अंधेरे का लाभ उठाकर एक आरोपी भागने में सफल रहा।पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक विशाल कंटेनर और तस्करों के पास से तीन एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है।आरोपियों की पहचान इमरान (निवासी- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश), मंसब अंसारी और सफीक अंसारी (दोनों निवासी- रंका, गढ़वा) के रूप में की गयी है।नवाबाजार थाना प्रभारी संजय कुमार यादव को गुप्त सूचना मिली थी कि गढ़वा के रास्ते पड़वा मोड़ होते हुए छतरपुर की तरफ एक बड़े कंटेनर में मवेशियों को लादकर बिहार ले जाया जा रहा है।सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाई और पुलिस बल के साथ नवाबाजार थाने के ठीक सामने चेक पोस्ट लगाकर तड़के ही नाकेबंदी कर दी।तड़के करीब 03:10 बजे एक संदिग्ध कंटेनर (बीआर24 जीसी 3133) आता हुआ दिखाई दिया।पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो वाहन रुकते ही उसमें सवार दो लोगों ने कूदकर भागने का प्रयास किया।हालांकि, मुस्तैद पुलिस जवानों ने खदेड़कर उनमें से एक को दबोच लिया।पकड़े गये आरोपियों की मौजूदगी में जब पुलिस ने कंटेनर के पिछले हिस्से को खुलवाया, तो अंदर का नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गये।कंटेनर के भीतर बेहद क्रूरता और बेरहमी के साथ मवेशियों को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था।जांच करने पर उसमें कुल 42 मवेशी पाये गये, जिनमें 29 भैंस और 13 भैंसे शामिल थे। वाहनों में हवा की कमी और अत्यधिक दबाव के कारण एक भैंस की दम घुटने से मौत हो चुकी थी।पुलिस ने तत्काल सभी जीवित 41 मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला और उनके चारे-पानी की व्यवस्था की।गिरफ्तार आरोपियों से कड़ाई से की गयी पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इन पशुओं को अवैध बाजार में बेचने के लिए गढ़वा से बारून (बिहार) ले जा रहे थे। उन्होंने पुलिस के सामने इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया है।पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस अवैध कारोबार के पीछे गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के दो बड़े सरगना सक्रिय हैं।इनमें जगीउल्लाह (पिता- भोला मियां) और अधर हुसैन (पिता- याकूब अंसारी) मुख्य भूमिका में हैं।इन्हीं के इशारे पर मवेशियों को जुटाकर बिहार और अन्य राज्यों में खपाया जाता है। पुलिस ने इस मामले में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कांड संख्या 29/26 दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को चिकित्सकीय जांच के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर डीसी ने स्टेडियम का निरीक्षण, पदाधिकारियों को मिला निर्देश

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन की तैयारियों को लेकर शनिवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने टूर्नामेंट से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु की जानेवाली तैयारियों के संबंध में संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान उपविकास आयुक्त संजय भगत, पुलिस अधीक्षक (यातायात), अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि व्यवस्था), उप निदेशक, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, जिला नजारत उपसमाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, मेजर आनंद प्रकाश, विद्युत विभाग, सिविल सर्जन कार्यालय सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने स्टेडियम परिसर, दर्शक दीर्घा, प्रवेश एवं निकास द्वार, वीआईपी एवं खिलाड़ियों की आवाजाही की व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन किया।

उन्होंने निर्देश दिया कि खिलाड़ियों, दर्शकों एवं अधिकारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं।उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि डूरंड कप देश का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है और रांची के लिए इसकी मेजबानी गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि आयोजन को सफल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ एक टीम की तरह कार्य करें, ताकि खिलाड़ियों, अधिकारियों एवं दर्शकों को बेहतर अनुभव प्राप्त हो तथा रांची एक उत्कृष्ट मेजबान के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके।

उपायुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि टूर्नामेंट के दौरान विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, संवेदनशील स्थलों की पहचान, सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश बिंदुओं पर प्रभावी जांच व्यवस्था तथा त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली सुनिश्चित की जाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया।यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने स्टेडियम एवं आसपास के क्षेत्रों में वाहनों के सुचारु परिचालन के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने संभावित यातायात दबाव को देखते हुए आवश्यकतानुसार डायवर्जन प्लान, साइन ऐज, पार्किंग प्रबंधन तथा यातायात कर्मियों की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्टेडियम के आसपास चिन्हित किए जा रहे पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि पार्किंग स्थलों का व्यवस्थित तरीके से निर्धारण किया जाए।उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को मैच के दौरान एम्बुलेंस, चिकित्सकों की टीम, प्राथमिक उपचार केंद्र एवं आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। साथ ही अग्निशमन, विद्युत एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को भी पूर्ण रूप से तैयार रखने को कहा ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

ट्रूथ पर्थ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक कुमार भारती के द्वारा डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, भास्कर प्रीटिंग प्रेस गोविंदपुर मेन रोड, अशोक नगर के.जी. आश्रम, धनबाद (झारखंड) से
मुद्रिक एवं नियर भाटिया शिव मंदिर, गांधी नगर धनबाद से प्रकाशित फोन नं. 7004605076, 9852421580
संपादकः- रवि रंजन * इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं सम्पादन हेतु पी आर बी एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उतरदायी। ई. मेलः-truthpath941@gmail.com आर. एन. आई.नंबर .-JHAHIN/2023/90593

संक्षिप्त खबरें

चोपन से उत्तर मध्य रेलवे के लिए माल रैक को डीआरएम ने दिखाई हरी झंडी

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबादः मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) अखिलेश मिश्र ने चोपन स्टेशन, चोपन कंट्रोल कार्यालय, एसीसी सीमेंट सलाईबनवा साइडिंग तथा चोपन पिट लाइन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्री एवं माल परिचालन व्यवस्था, संरक्षा मानकों, उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं तथा रखरखाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परिचालन में सुरक्षा, समयबद्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के साथ-साथ उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिया। निरीक्षण के उपरांत मंडल रेल प्रबंधक ने चोपन से चुनार मार्ग होते हुए उत्तर मध्य रेलवे के लिए प्रेषित 100वें लॉन्ग हॉल माल रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह उपलब्धि धनबाद मंडल की उत्कृष्ट परिचालन क्षमता, विभागों के समन्वित प्रयास तथा माल परिवहन को गति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे न केवल माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि औद्योगिक इकाइयों को भी समयबद्ध एवं विश्वसनीय रेल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर मंडल के अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे ।

तेलमोच्चो में नीम पेड़ की टहनी से लटकता मिला अज्ञात युवक का शव

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबादः तेलमच्चो के नूतनडीह कुंजी के जंगल में शनिवार की सुबह 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव नीम के पेड़ की टहनी से शर्ट के सहारे लटक रहा था। शव के पैर से टपक रहे खून को देख लोग हत्या की आशंका जताते देखें गए। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तहकीकात की। शव मिलने की सूचना पाकर आसपास गांव से काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन समाचार लिखे जाने तक किसी ने भी शिनाख्त नहीं की। पुलिस पंचनामा तैयार कर शव को कब्जे में लेकर थाना ले आई है।

मेगा टिकट चेकिंग अभियान में वसूला गया 10 लाख रुपए

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबादः धनबाद मंडल में शनिवार को मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया. यह टिकट चेकिंग अभियान सुनियोजित कार्यक्रम के तहत दिन-रात चलाया गया. जांच अभियान में 796 यात्रियों को पकड़ा गया। इसमें बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री, बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले यात्री, बिना बुक किये गए सामान के साथ यात्रा कर रहे यात्रीगण शामिल थे. उनसे 07,50,810 रुपए जुमार्ने के रूप में वसूला गया। तथा पकड़ें गए यात्रियों को उचित टिकट के साथ यात्रा करने की हिदायत दी गई.

बाघमारा में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का निरीक्षण

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबादः निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बाघमारा विधानसभा क्षेत्र-सह-निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, धनबाद के निदेर्शानुसार आज बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' कार्य का क्षेत्रीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा करना और इसमें पारदर्शिता व सटीकता सुनिश्चित करना था। अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस विशेष निरीक्षण अभियान का नेतृत्व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा किया गया। टीम ने निर्धारित शिड्यूल के अनुसार सुबह से शाम तक विभिन्न नगर निगम और पंचायत क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हकीकत का जायजा लिया और अधिकारियों व बीएलओ के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

प्रशिक्षण से स्कूलों में बेहतरीन शैक्षणिक माहौल का होगा निर्माण : डीसी

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबादः शिक्षकों को बेहतर और सकारात्मक मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से एमटीसी सभागार में झरिया प्रखंड के सभी प्राथमिक, मध्य, उच्च, उच्चतर माध्यमिक एवं आवासीय 108 विद्यालयों के 211 प्रभारी प्रधानाध्यापकों एवं सहायक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन करते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने कहा कि इस प्रशिक्षण से स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा, कुशल प्रबंधन और एक बेहतरीन शैक्षणिक माहौल का निर्माण होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल का मुख्य ध्येय शिक्षा के स्तर में सुधार करना और बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। इस

तरह के कार्यक्रमों से शिक्षकों को सकारात्मक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे वे कुशल स्कूल प्रबंधन में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। बेहतर मार्गदर्शन मिलने से शिक्षक स्कूलों में न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेंगे, बल्कि बच्चों के लिए एक सकारात्मक और कुशल प्रबंधन युक्त वातावरण भी तैयार कर सकेंगे। प्रशिक्षण के दौरान विद्यालयों की आधारभूत संरचना के रख-रखाव, बाल-मित्र आधारित परिसर के निर्माण, बेहतर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के प्रभावी उपयोग तथा गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के संचालन सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही, इन सभी पहलुओं के माध्यम से विद्यालय परिसर में बच्चों के लिए सुरक्षित, आकर्षक, आनंददायक एवं खु-शहाल शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

होटल बैद्यनाथ विहार में ऑल इंडिया स्माल एंड मिडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की नई जिला कमेटी का गठन

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबादःऑल इंडिया स्माल एंड मिडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की देवघर जिला कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को होटल बैद्यनाथ विहार में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से पुरानी जिला कमेटी को भंग करते हुए नई जिला कमेटी का विधिवत गठन किया गया। बैठक में प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार सिंह पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे, जबकि धनबाद जिला अध्यक्ष राहुल कुमार सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें राजेश किशोर को संरक्षक, वरुण कुमार को जिला अध्यक्ष, बबलू साह एवं गोपाल शर्मा को उपाध्यक्ष, शैलेंद्र मिश्रा को महासचिव, उपेंद्र बरनवाल एवं पंकज सिंह को सचिव, अरुण केसरी को कोषाध्यक्ष, धनंजय कुमार राणा को सह-कोषाध्यक्ष, पप्पू यादव को कानूनी सलाहकार (विधि सलाहकार) तथा रंजन कुमार को जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी बनाया गया।कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चमन कुमार, परमजीत कुमार, दिवाकर यादव, आशुतोष झा, मंटू यादव, सुधांशु शेखर, मो. अमजद, सुजीत सिंह, जयदीप तिवारी, अतुल गौतम एवं रमेश झा को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार सिंह ने कहा कि देवघर जिला कमेटी का गठन संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि नई टीम पत्रकारों के हितों की रक्षा, संगठन के विस्तार तथा पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करेगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से संगठन की मजबूती एवं पत्रकार एकता के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।

लायंस क्लब बाघमारा सेंटेनियल का चार्टर समारोह संपन्न

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबादः लायंस क्लब बाघमारा सेंटेनियल का 9 वां चार्टर सह 10 वां पदस्थापन समारोह बीसीसीएल गेस्टहाउस, डुमरा में शुक्रवार देर रात हुआ। कार्यक्रम की शुरूआत चार्टर सदस्यों द्वारा केक काटकर की गई। मुख्य अतिथि द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ सुजीत कुमार एवं क्लब के संरक्षक (पैट्रन) सह बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इंस्टालेशन चेयरपर्सन एमजे-एफ मदन मोहन ने अपने स्वागत भाषण से सभी आगंतुक अतिथियों और सदस्यों का अभिनंदन किया. समारोह के दौरान पीएमजेएफ लायन गणेश प्रसाद सिंह ने क्लब में शामिल हुए 6 नए सदस्यों को इंडक्शन दिलाया और उन्हें क्लब की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। पास्ट काउंसिल चेयरपर्सन सह इंस्टॉलिंग ऑफिसर एमजेएफ लायन मधुकर सिन्हा ने अध्यक्ष दीपक प्रसाद, सचिव शंकर नापित एवं कोषाध्यक्ष पालचन्द महतो सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद सचिव विक्की रवानी ने क्लब का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। समारोह में बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, मुख्य अतिथि सुजीत कुमार, शशिकांत शरण एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष लायन दीपक प्रसाद ने अपने विचार साझा करते हुए क्लब के सेवा कार्यों की सराहना की और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से मदन मोहन महतो एवं गोपाल सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन नागेन्द्र साव ने किया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न क्लबों से आये गणमान्य लायंस पदाधिकारियों, अतिथियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। मौके पर सुमन कुमार, संतोष कुमार, जितेंद्र कुम्हार, बंटी सोनार, गुड्डू सोनी, दिलीप गुप्ता, लक्ष्मण रवानी, आशा शरण, सुबोध कुमार, सुनीता कुमारी, राजीव रंजन, अशोक राय, विजय साव, लालचंद ठाकुर, उषा देवी, विजय सोनी, सावित्री पाल, डॉ बिनोद कुमार मिश्रा, डॉ. आशीष कुमार, रंजीत कुमार, सोरेन महतो, समीर लाला, कालीचरण पाल, सोमनाथ पूर्ती , दिनेश पूरी, गिरधारी लाल अग्रवाल, प्रशांत पांडेय, डॉ स्वतंत्र कुमार, किरण चावड़ा ,डॉ मुकेश कुमार राय, डॉ आरके शर्मा, रोशन अग्रवाल , राजेश जायसवाल आदि मौजूद थे ।

सीएम एसओई की तर्ज पर विकसित होंगे जिले के 464 स्कूलः डीसी

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबादः लिए जिले के 464 स्कूल सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस (सीएम एसओई) की तर्ज पर विकसित होंगे। इसकी तैयारी चल रही है। जल्द ही सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके लिए स्कूल में अतिरिक्त क्लास रूम, गर्ल्स- ब्वॉयज के लिए अलग-अलग शौचालय, बाउंड्री वॉल, स्पोर्ट्स ग्राउंड, पार्किंग, भोजनालय, डायनिंग एरिया, मल्टीपरपज हॉल, बेंच-डेस्क, वाटर कूलर, हेल्थ किट, स्पोर्ट्स किट सहित उच्च गुणवत्ता की व्यवस्था बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त जानकारी डीसी आदित्य रंजन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इसका आयोजन ड-ीसी ऑफिस के सभागार में किया गया था। डीसी ने एक वर्ष में जिला प्रशासन द्वारा स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व सुधारों, बदलावों और ढांचागत परिवर्तनों की भी जानकारी दी। ड-ीसी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिला स्तरीय टीम द्वारा विद्यालय में किए गए विभिन्न नवाचारों एवं प्रयासों के आधार पर नो कॉस्ट, लो कॉस्ट पर आधारित 200 अंकों का मूल्यांकन किया गया। इसमें जिन विद्यालयों ने 180 या उससे अधिक अंक प्राप्त किया उनका हाई कास्ट में मूल्यांकन कर विद्यालयों को आवश्यकता के अनुसार सिविल कार्यों से लेकर विभिन्न आपूर्ति सामग्री तक उपलब्ध कराई गई।

जबकि जिन विद्यालयों को मानकों के अनुसार अंक नहीं मिले उन्हें आवश्यक सुझाव देकर सुधारात्मक प्रयास के लिए प्रेरित किया गया। डीसी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में धनबाद जिले को अव्वल बनाने के उन्होंने बताया कि छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए बोर्ड परीक्षा से पहले दो बार प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया। होनहारों को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। इस पहल का सकारात्मक परिणाम यह रहा कि बोर्ड परीक्षा में धनबाद जिला राज्य के शीर्ष 10 जिलों में शामिल रहा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 21 विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिक-ाओं को ब्लेजर, प्रमाण पत्र, मोमेंटो और इंपैक्ट किट देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया विद्यालयों में बच्चों के लिए खुशहाल एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ। इसमें शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के नैतिक मूल्यों के विकास एवं चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया गया। साथ में विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं स्वच्छता में बदलाव आया। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में बढ़ोत्तरी हुई। डीसी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेताजी आवासीय विद्यालय के 130 छात्रों को बेहतर सुविधाओं के साथ नए कैंपस में शिμट किया गया। नए कैंपस में नेताजी भवन का निर्माण जारी है तथा इसमें शिक्षक सहित आठ लोगों की नियुक्ति की गई है। विद्यार्थियों की विद्यालय तक आसान पहुंच के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20000 साइकिल का वितरण किया गया। जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10470 व उससे पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9989 साइकिल का वितरण हुआ था। समय की मांग को देखते हुए जिले में 10 स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का लक्ष्य है। इसमें चार को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा कार्य जारी है। शेष 5 लाइब्रेरी की स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है। बताया कि आरएस मोर कॉलेज गो-विंदपुर, बीबीएम इंटर कॉलेज बलियापुर, सिंदरी कॉलेज सिंदरी एवं पांडरपाला वासेपुर में स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी की स्वकृति प्रदान की गई है। जबकि कतरासगढ़ डीएमसी भवन, टुंडी डिग्री कॉलेज, चिरकुंडा नगर परिषद, तोपचांची ब्लॉक में गोमो के तहत विवाह मंडप एसएचएमएस चिरकुंडा में स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। उच्च शिक्षा को बढ़-ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थाओं को जिला प्रशासन ने जमीन उपलब्ध कराई है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं की बेश-ाकीमती सरकारी जमीन के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाकर उसे सुरक्षित कर लिया है। डीसी ने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा सरकार और प्रश-ासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी उद्देश्य के साथ, क्षेत्र के 59 जर्जर विद्यालयों को चिन्हित कर उनके जीर्णोद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। डीसी ने बताया कि ग्रामीण, गरीब और पिछड़े वर्ग के युवाओं को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से टुंडी स्थित अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास को कल्याण गुरुकुल में परिवर्तित किया गया है। यहां युवाओं को पूरी तरह से निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। 45 दिन के प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्लेसमेंट उपलब्ध कराया जाता है। पत्रकार वार्ता में उप विकास आयुक्त सन्नी राज के अलावा शिक्षा विभाग, डीएमएफटी टीम तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे।

डीसी ने तोपचांची से एमएनसीयू आए परिजनों से ली फीडबैक

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबादःउपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने आज एमटीसी सभागार में आयोजित प्र-शिक्षण कार्यक्रम से पहले एमएनसीयू वार्ड में भर्ती बच्चों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त ने विशेष रूप से तोपचांची प्रखंड से इलाज के लिए आए एक नवजात शिशु के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से सीधे बातचीत कर अस्पताल द्वारा दिए जा रहे इलाज, दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सा कर्मियों के व्यवहार के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। परिजनों ने

उपायुक्त को बताया कि बच्चे को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल रही है और डॉक्टर लगातार उस-ाकी निगरानी कर रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि एमएनसीयू में आने वाले हर बच्चे को उच्च स्तरीय चिकित्सा देने का निर्देश दिया गया है। साफ-सफाई, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता और अन्य व्यवस्था में कोई कमी नहीं होने देने का भी निर्देश दिया है।

जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 5 लाख 45 हजार 869 ईएफ का हुआ वितरण

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबादः जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन के निदेर्शानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एस-ाआइआर 2026) के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म (ईएफ) का वितरण जारी है।इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि धनबाद जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को ईएफ वितरण का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक 5 लाख 45 हजार 869 मतदाताओं को ईएफ वितरित किया जा चुका है।ईएफ वितरण की विधानसभा वार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ईएफ वितरण में टुंडी सबसे आगे है। जहाँ 1,29,734 ईएफ बांटे जा चुके हैं। वहीं दूसरे स्थान पर निरसा है। निरसा में 1,02,067 ईएफ का वितरण किया गया है। जबकि सिंदरी में 1,00,025 ईएफ का वितरण पूरा हो चुका है। वहीं धनबाद विधानसभा में 78,687, झरिया में 71,400 तथा बाघमारा में 63,956 ईएफ का वितरण किया गया है।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ईएफ वितरण के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने-अपने विधानसभा में मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं, ताकि इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

कोयला चोरी व अवैध खनन पर रोक के लिए केंद्र देगा हरसंभव सहयोग : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

धनबादःधनबाद में कोयला चोरी और अवैध खनन का मामला अब सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कोयला चोरी रोकने के लिए दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। बैठक में कोयला चोरी, अवैध खनन और खनन क्षेत्रों की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। गृह राज्य मंत्री ने इन चुनौतियों के प्रभावी समाधान के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अवैध खनन, कोयला चोरी तथा अन्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के प्रभावी समाधान के लिए भारत सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि कोकिंग कोयला देश के लिए महत्वपूर्ण खनिज है और इसके सुरक्षित एवं सतत उत्पादन के लिए अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना केंद्र

सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षित एवं निर्बाध घरेलू कोकिंग कोयला उत्पादन राष्ट्रीय सामरिक महत्व का विषय है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल शुक्रवार को दिल्ली में भेंट की थी। सीएमडी ने बीसीसीएल की खनन गतिविधियों की सुरक्षा, कोकिंग कोयले के स-ुरक्षित एवं निर्बाध उत्पादन तथा इसके लिए आवश्यक सुरक्षा संबंधी उपायों पर विस्तृत चर्चा की। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भारत की आयातित कोकिंग कोयले पर निर्भरता कम करने में बीसीसीएल की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कोकिंग कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर बीसीसीएल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने दोहराया कि कोकिंग कोयले का सुरक्षित एवं निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाना जरूरी है।

04-07-2026 T.P. Page 4_Layout 1 05-07-2026 07:54 Page 1

संक्षिप्त खबरें

तीन युवकों की मौत पर उबाल, संथाल समाज ने बेरमो एसडीओ कार्यालय के घेराव का किया ऐलान

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची/बोकारो : झारखंड के बोकारो जिले में तीन संथाल युवकों की मौत के बाद आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। संथाल समुदाय ने घटना के विरोध में बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। समुदाय के नेताओं का कहना है कि मृतकों के परिजनों को न्याय दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

संथाल समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि तीनों युवकों की मौत की परिस्थितियां बेहद संदिग्ध हैं और अब तक मामले में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। समाज के नेताओं का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों की नजर अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। संथाल समाज का कहना है कि जब तक मृतकों के परिजनों को न्याय नहीं मिलता और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच प्रशासन और समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच संवाद की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे तनावपूर्ण स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके।

लातेहार एसपी ने की मासिक अपराध गोष्ठी की समीक्षा

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

लातेहर : जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में शनिवार को पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया।पुलिस अधीक्षक ने गोष्ठी में पिछले माह में घटित सभी महत्वपूर्ण अपराधों की समीक्षा की।पुलिस अधीक्षक श्री कुमार ने लंबित कांडों का निष्पादन करने और अपराध नियंत्रण के लिए समन्वय स्थापित कर कार्य करने की बात कही।बैठक के दौरान उन्होने पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन, ई डार एंट्री, मालखाना प्रभार एवं सीईआईआर पोर्टल का उपयोग की समीक्षा की।एसपी ने पिछले माह में हत्या, लूट, बलात्कार,पोक्सो आदि के कांडों में गिरफ्तारी एवं उद्भेदन के संबंध में किए गए प्रयासों की गहन समीक्षा की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया।बैठक में पिछले एक वर्ष में फरार अपराधियों, दागी पंजी और गृहभेदन के मामलों पर विस्तृत समीक्षा कर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश सम्बंधित पुलिस पदाधिकारियों को दिया।इस गोष्ठी में जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, थाना प्रभारी एवं सभी शाखा के प्रभारी मौजूद थे।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की उपायुक्त ने की समीक्षा, कैंप मोड में लक्ष्यवार कार्य करने का दिया निर्देश

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पलामू : उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर एवं बीएलओ सुपरवाइजरों से गणना प्रपत्र के वितरण, प्राप्त प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन तथा अब तक की कार्य प्रगति की विस्तृत जानकारी ली।उपायुक्त ने समीक्षा के दौरान विभिन्न बीएलओ से सीधे संवाद कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने अपने समक्ष बीएलओ से गणना प्रपत्र भरवाकर पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।इस दौरान डालटनगंज विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीएलओ प्रशिक्षण के अनुरूप पूरी सावधानी एवं शुद्धता के साथ गणना प्रपत्र भरने एवं डिजिटाइजेशन का कार्य सुनिश्चित करें।उपायुक्त श्री शेखावत ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता एवं विश्वसनीयता से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों को लक्ष्यवार एवं कैंप मोड में कार्य करते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर गणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।उन्होंने सभी बीएलओ सुपरवाइजरों को नियमित रूप से कार्यों की मॉनिटरिंग करने तथा किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्य करें, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

पूर्व सीएम रघुवर दास और विधायक पूर्णिमा साहू ने भरा वोटर लिस्ट सुधार फॉर्म धालभूम एसडीओ ने खुद दिया प्रपत्र

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पूर्वी सिंहभूम : वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)-2026 अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक पूर्णिमा साहू को उनके गणना प्रपत्र (फॉर्म) उपलब्ध कराये गये। दोनों जनप्रतिनिधियों ने नियम के अनुसार अपने-अपने फॉर्म को भरकर अधिकारियों को सौंप दिया।इस मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह धालभूम एसडीओ अर्नव मिश्रा और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्वयं मौजूद रहे।एसडीओ अर्नव मिश्रा ने कहा कि निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का सही होना बेहद जरूरी है।उन्होंने जिले के सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने बीएलओ को फॉर्म और जरूरी दस्तावेज सौंपकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराये ताकि त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सके।

कैडर स्थानांतरण से आये अधिकारी राधेश्याम प्रसाद को बड़ी राहत, वरीयता घटाने का सरकार का आदेश निरस्त

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राधेश्याम प्रसाद की ओर से राज्य सरकार द्वारा वरीयता घटाने के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर फैसला सुनाया।अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार द्वारा उनकी वरीयता घटाने के आदेश को निरस्त कर दिया है।अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर आपसी सहमति से कैडर स्थानांतरण के मूल आदेश में वरीयता खोने की कोई शर्त नहीं थी, तो सरकार बाद में इसे पिछली तिथि से लागू नहीं कर सकती है। अदालत ने कहा कि जब 2006 में प्रार्थी का कैडर स्थानांतरण हुआ, तब बिहार व झारखंड राज्यों के बीच ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि वे अपनी वरीयता खो देंगे। सरकार अपने 2008 के नीतिगत फैसले को 2006 के मामलों पर पिछली तिथि

से लागू नहीं कर सकती। इतना ही नहीं बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 73 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारी की सेवा शर्तों में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जो उसके लिए नुकसानदेह हो। अदालत ने झारखंड सरकार द्वारा जारी 23 सितंबर 2024 के आदेश व 16 दिसंबर 2024 को जारी अंतिम वरीयता सूची (जहां प्रार्थी को नीचे धकेला गया था) को निरस्त कर दिया।अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि राधेश्याम प्रसाद की मूल वरीयता (क्रमांक 835-बी) को सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल किया जाये।बिहार पुनर्गठन अधिनियम -2000 के तहत बिहार व झारखंड के बीच सरकारी कर्मचारियों के कैडर का बंटवारा किया गया था। प्रार्थी राधेश्याम प्रसाद व एक अन्य कर्मचारी मंजू प्रसाद ने आपसी सहमति से बिहार से झारखंड तथा झारखंड से बिहार कैडर के लिए संयुक्त आवेदन दिया था।दोनों राज्य सरकारों की सहमति के बाद 21 जून 2006 को प्रार्थी को झारखंड कैडर आवंटित किया गया।इस मूल आदेश में यह कहीं भी नहीं लिखा था कि उन्हें अपनी बैच की वरीयता गंवानी होगी।इसके बाद झारखंड सरकार ने उन्हें सामान्य वरीयता सूची में क्रमांक 835-बी पर रखते हुए वर्ष 2011, 2016 और 2023 में संयुक्त सचिव के पद तक प्रोन्नति भी दीं। 19 जुलाई 2008 को झारखंड सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया कि आपसी तबादले पर आनेवाले कर्मचारियों को उनके बैच में सबसे नीचे रखा जायेगा।इसी निर्णय के सरकार ने 23 सितंबर 2024 को एक नया पत्र जारी कर प्रार्थी की वरीयता 835-बी से घटना कर 877-डी कर दिया था, जिसको याचिका दायर कर चुनौती दी गयी थी।

प्रदीप कुमार बलमुचू दोबारा बने इंटक,ददई गुट के प्रदेश अध्यक्ष

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

रांची : झारखंड प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) की कार्यकारिणी बैठक एवं महाधिवेशन शनिवार को राजधानी में आयोजित किया गया।इसमें पूर्व सांसद प्रदीप कुमार बलमुचू को दुबारा इंटक(ददई), झारखंड का अध्यक्ष चुना गया।बैठक के मुख्य अतिथि इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्री धीरज प्रसाद साहू थे।कार्यक्रम का संचालन इंटक के राष्ट्रीय महासचिव एनजी अरुण ने किया।वक्ताओं ने स्वर्गीय चंद्रशेखर दुबे के संघर्षपूर्ण जीवन एवं मजदूर हितों के लिए उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।तय किया कि इंटक मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई को और अधिक मजबूत एवं धारदार बनाएगा।महाधिवेशन में झारखंड के सभी जिलों से इंटक प्रतिनिधियों के साथ-साथ सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, सेल, लोहरदगा बॉक्साइट माइंस, चिड़िया माइंस (चाईबासा), नोवामुंडी माइंस (चाईबासा) सहित विभिन्न औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों के श्रमिकों ने हिस्सा लिया।बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं, श्रमिक अधिकारों तथा केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम संहिताओं पर विस्तार से चर्चा की।वक्ताओं ने कहा कि यदि इन श्रम कानूनों को वर्तमान स्वरूप में लागू किया गया तो इससे देश के करोड़ों मजदूरों के अधिकार कमजोर होंगे। सभी प्रतिनिधियों ने श्रमिक हितों की रक्षा हेतु एकजुट होकर संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया।कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री डॉ इरफान अंसारी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी, विधायक रामचंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष आरएन चौबे, कालीचरण यादव, युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा, रमेश कुमार झा, राहुल कुमार विश्वकर्मा, मनोज दास, आरपी सिंह, बच्चन पांडे, सुधांशु शेखर झा, खजांची राम, उदय प्रताप सिंह, ओमप्रकाश प्रजापति, जिया आलम आदि मौजूद रहे।

मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता: प्रशिक्षु आइएएस

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

बोकारो : डीसी अजय नाथ झा के निर्देश पर शनिवार को प्रशिक्षु आईएएस अरविंद राधाकृष्णन ने कैंप दो स्थित सदर अस्पताल का निरीक्षण किया।उपाधीक्षक डॉ एनपी सिंह, आइसीयू-सीसीयू इंचार्ज डॉ सौरव सांख्यान के साथ अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ व समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है।इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को संवेदनशीलता बरतनी चाहिए।बेहतर समन्वय व प्रभावी प्रबंधन के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। दुर्लभ रोगों के उपचार संबंधी सुविधाओं की सूची प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाये।आम नागरिकों को दुलर्भ सेवाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त हो। परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अविलंब वेटिंग एरिया शुरू करे।पीआईसीयू (पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट) का संचालन में देर नहीं करे।इससे पूर्व ओपीडी, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस वार्ड, थैलेसिमिया वार्ड सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में प्रशिक्षु आईएएस ने अस्पताल की कार्यप्रणाली की समीक्षा की।मरीजों को बेहतर व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई जरूरी निर्देश भी दिये।फामेर्सी में दो कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने, पुरुष व महिला मरीजों के लिए अलग-अलग कतार की व्यवस्था करने व अस्पताल परिसर की नियमित साफ-सफाई बनाये रखने का निर्देश दिया।

जिले के सभी प्रखंडों में शुरू हुआ जन समाधान दिवस,चैनपुर से उपायुक्त ने किया शुभारंभ

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

पलामू : पलामू जिले में आमजनों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब प्रत्येक शनिवार को सभी प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में जन समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में शनिवार को उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने चैनपुर प्रखंड कार्यालय में जन समाधान दिवस का शुभारंभ किया।कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर सबसे अधिक शिकायतें भूमि संबंधी मामलों से जुड़ी प्राप्त हुईं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश

दिया।उपायुक्त श्री शेखावत ने कहा कि प्रत्येक बुधवार को समाहरणालय में जन समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। कई लोगों को 50 से 90 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। आमजनों को इस असुविधा से राहत देने तथा उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी प्रखंडों एवं अंचलों में जन समाधान दिवस की शुरूआत की गई है।उन्होंने बताया कि प्रत्येक शनिवार को आयोजित जन समाधान दिवस के उपरांत संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रत्येक गुरुवार को प्राप्त आवेदनों एवं उन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे, ताकि शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।जन समाधान दिवस में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं एवं आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। इस दौरान संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

रमना में अवैध गांजा की खेती का भंडाफोड़, 118 किलो पौधा जब्त

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

गढ़वा : रमना थाना क्षेत्र के बुल्का गांव स्थित गजनिया टोला में पुलिस ने अवैध गांजा की खेती का भंडाफोड़ किया है।पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को रमना थाना पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्र में लगी गांजा की फसल को नष्ट कर दिया।कार्रवाई के दौरान कुल 118 किलोग्राम गांजा के पौधे जब्त किए गए। पुलिस ने मामले में सनहा दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, बुल्का गांव के गजनिया टोला निवासी संजय यादव (पिता- परमेश्वर यादव) द्वारा अपने अर्धनिर्मित मकान के परिसर में अवैध रूप से गांजा की खेती किए जाने की सूचना पुलिस अधीक्षक को मिली थी।

सूचना के सत्यापन के बाद अंचलाधिकारी विकास पाण्डेय की देखरेख में रमना थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की।छापेमारी के दौरान अर्धनिर्मित मकान के परिसर

में बड़े पैमाने पर गांजा के पौधे लगे मिले।अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद पौधों को उखाड़कर जब्त कर लिय

जब्त पौधों का कुल वजन 118 किलोग्राम पाया गया।इसके बाद विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरी फसल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, ताकि इसका किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके।पुलिस ने इस मामले में रमना थाना में सनहा दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि अवैध खेती में अन्य लोगों की संलिप्तता तो नहीं है। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की अवैध खेती और तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी अभियान में अंचलाधिकारी विकास पाण्डेय, थाना प्रभारी आकाश कुमार, पुअनि आलोक कुमार, सअनि मोहम्मद सलीम अंसारी, राजस्व कर्मचारी आलोक कुमार सिंह सहित पुलिस एवं प्रशासन के अन्य अधिकारी और जवान शामिल थे।

नल-जल योजना फ्लॉप, चुंआ खोदकर प्यास बूझा रहे लोग डोमचांच प्रखंड के सुदूरवर्ती ढाब पंचायत के गांवों की स्थिति

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

कोडरमा : सरकार की महत्वाकांक्षी नल-जल योजना का लाभ प्रखंड के सुदूरवर्ती ढाब पंचायत के कई गांवों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है।योजना के तहत लगाया गया जलमीनार का अलग-अलग सिस्टम लंबे समय से खराब पड़ा है।ऐसे में मडवाटांड, बूढ़ीया और वंदना गांव के ग्रामीण गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। स्थिति यह है कि मडवाटांड के नीचे टोला के लोगों को पीने के पानी के लिए नदी में चुंआ (छोटा गड्ढा) खोदना पड़ रहा है।उसी में रिसकर जमा होने वाले पानी को ग्रामीण पीने और घरेलू उपयोग में ला रहे हैं।ऐसे समय में जब मानसून की शुरूआत हो चुकी है तब भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।ग्रामीणों का कहना है कि जलमीनार खराब होने की शिकायत कई बार संबंधित विभाग को की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.लोगों के अनुसार कहीं मोटर खराब है तो कहीं सोलर प्लेट का सिस्टम खराब हो चुका है।गांव की कुंती देवी ने बताया कि मजबूरी में नदी के चुंआ का पानी पीना पड़ता है।इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं।मडवाटांड की कुंती देवी के अलावा काजल देवी, कारी मसोमात, बुडिया टोला की सुनीता देवी, आनार देवी, रामकिसुन भुइंया, अशोक रविदास, शैलेंद्र भुइंया, दिलीप भुइंया, राजकुमार भुइंया, बंदना टोला के नुनूलाल भुइंया, रामविलास भुइंया व रेखा देवी ने बताया कि प्रशासन को अविलंब जलमीनार की मरम्मत कर हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए। लोगों ने बताया कि जब तक पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होती, तब तक उन्हें नदी में चुंआ खोदकर पानी पीने की मजबूरी झेलनी पड़ेगी।पंचायत अंतर्गत कुछ टोला में जलमीनार की मरम्मत और पेयजल व्यवस्था बहाल करने के लिए कई बार पीएचईडी से आग्रह किया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।

विद्यालय में कुव्यवस्था के खिलाफ ग्रामीणों ने की बैठक

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

गिरिडीह : शिक्षा के मंदिर में प्रबंधन समिति की मनमानी एवं कुव्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।शनिवार को एकजुट ग्रामीणों ने विद्यालय में कुव्यवस्था में सुधार एवं अन्य मुद्दों को ले आपात बैठक की।मामला उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाँकी कला की है। जानकारी के अनुसार शनिवार को ग्रामीणों की एक बैठक उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाँकी कला में हुई।बैठक में ग्रामीण प्रधानाध्यापक की कार्यशैली से नाराज दिखे और व्यवस्था में सुधार की मांग रखी।ग्रामीण अफजल अंसारी,मोहम्मद इनाम,सिराज अंसारी,आरिफ अंसारी,दिलचंद महथा,तैयब अंसारी, निसार अंसारी,असजद अंसारी,रहमत अंसारी,सलीम अंसारी,कलीम अंसारी,रियाज अंसारी,शहाबुद्दीन अंसारी,जमील अंसारी,बाबूजन अंसारी आदि ने कहा कि यहां करीब 4 सौ छात्र छात्राएं नामांकित हैं लेकिन सौ डेढ़ बच्चे भी स्कूल नहीं आते हैं।उर्दू स्कूल होने के बाद भी यहां उर्दू पुस्तक की कमी है।यहां एमडीएम में मनमानी का आलम यह है कि ब्लैंक चेक में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष,संयोजिका के हस्ताक्षर लेकर राशि का बंदर बांट किया गया है। स्कूल में कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है।यहां शौचालय/पेयजल की व्यवस्था नहीं रहने से बच्चों को काफी परेशानी होती है।ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक से व्यवस्था में सुधार की मांग की। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे प्रखंड व जिला स्तरीय पदाधिकारी से शिकायत करेंगे।विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक विनोद हेंब्रम ने कहा कि शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जा रहा है।कम उपस्थिति को ले वे स्वयं गांव भ्रमण कर अभिभावकों को प्रेरित कर रहे हैं।स्कूल में शौचालय व पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दू पुस्तक के लिए विभाग को पत्राचार किया गया है।ब्लैंक चेक में हस्ताक्षर प्रकरण पर कहा कि यह मामला उनके कार्यकाल का नहीं है।

स्कूल में फुटबॉल खेल रहे बच्चों पर गिरा 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन तार, बाल-बाल बचे बच्चे

ट्रूथ पथ प्रतिनिधि

गुमला : गुमला के भरनो प्रखंड मुख्यालय स्थित सीताराम साव सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को एक बड़ी दुर्घटना होते-होते टल गयी।स्कूल में लंच के समय जब बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। तभी अचानक 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर जमीन पर आ गिरा।तार में विद्युत प्रवाहित होने के कारण उसमें तुरंत आग लग गयी और चिंगारियां निकलने लगीं।तार को गिरता देख मैदान में खेल रहे बच्चों ने सूझबूझ दिखायी और किसी तरह भागकर स्कूल भवन के अंदर चले गये। इसी दौरान वहां से गुजर रहा एक स्कूटी सवार व्यक्ति भी चालू तार की चपेट में आने से बाल-बाल बच गया।घटना के बाद पूरे विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी और डर का माहौल

बन गया। स्कूल के शिक्षकों ने बिना समय गंवाये तुरंत बिजली विभाग के कर्मियों को मामले की जानकारी दी।सूचना मिलते ही पावर हाउस से बिजली आपूर्ति बंद की गयी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना से आक्रोशित विद्यालय के शिक्षकों और स्थानीय ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है।ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के ठीक पास से सालों पहले यह हाईटेंशन लाइन गुजरी थी, जिसके तार अब बेहद जर्जर हो चुके हैं।विभाग को बार-बार सूचित करने के बाद भी इन्हें बदला नहीं जा रहा है।बारिश के इस मौसम में जर्जर तारों के टूटने का खतरा और बढ़ गया है, जिससे मासूम बच्चों की जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है। बहरहाल, बिजली विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर टूटे हुए तार की मरम्मत कर दी है, जिसके बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गयी। स्थानीय लोगों ने विभाग से स्कूल के पास से गुजरने वाले तारों को जल्द से जल्द बदलने या इन्हें कवर करने की मांग की है।

संक्षिप्त खबरें

पलंग पर सो रही महिला को जहरीली सांप ने डसा, इलाज के दौरान मौत

गुरपा कोलटीन गांव की सपना देवी की मगध मेडिकल अस्पताल में हुई मौत

घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम, गांव में शोक की लहर

फतेहपुर (गया जी)(एजेंसी) : फतेहपुर प्रखंड के गुरपा कोलटीन गांव में सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान गांव निवासी गणेश मांझी की पत्नी सपना देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि पूरे गांव में शोक का माहौल है।मिली जानकारी के अनुसार, सपना देवी शुक्रवार देर रात अपने घर में पलंग पर सो रही थीं। इसी दौरान एक जहरीला सांप पलंग पर चढ़ गया और उन्हें डस लिया। कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया रेफर कर दिया। परिजन उन्हें तत्काल गया लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।बताया गया है कि जिस सांप ने महिला को डंसा उसे घर वालों ने मार डाला है। इधर, महिला की मौत की खबर मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव में भी घटना को लेकर शोक की लहर है।

पाटलिपुत्र रेल परिसर के आरेख उद्यान में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित

हाजीपुर(एजेंसी) : पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन, हाजीपुर की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता सिंह के नेतृत्व में आज पाटलिपुत्र रेल परिसर के आरेख उद्यान में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों के द्वारा पौधारोपण कराया गया । इस अवसर पर बच्चों को पौधों के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी संगठन की अध्यक्षा के द्वारा प्रदान की गई एवं प्रत्येक बच्चों को उपहार स्वरूप ह्यह्यपॉटेड प्लांटह्यह्य दिया गया। इस अवसर पर संगठन की उपाध्यक्षा श्रीमती रंजना कुमार, सचिव श्रीमती मनीषा सिन्हा, संयुक्त सचिव श्रीमती प्रियंका सिंह तथा कार्यकारिणी की सभी सदस्याएं तथा महिला कल्याण संगठन, दानापुर की कार्यकारिणी की सभी सदस्याएं उपस्थित थीं।

अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति पर जोर

अररिया (एजेंसी) : प्रखंड क्षेत्र के तिरसकुंड पंचायत के प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टोला, मधुरा में शनिवार को अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की छात्रा मुस्कान हेंब्रम की माता शनिचरी देवी ने की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरीय शिक्षक कुमार राजीव रंजन ने कहा कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे नियमित रूप से अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके।प्रधान शिक्षक मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालय की प्रगति में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे प्रतिदिन शाम को अपने बच्चों की कॉपियाँ अवश्य जांचें तथा विद्यालय में पढ़ाए गए कार्यों की जानकारी लें। इससे सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज में फैली भ्रांतियाँ दूर होंगी और अधिक से अधिक बच्चे विद्यालय से जुड़ेंगे।इस अवसर पर फोकल शिक्षक संजीत कुमार निगम ने सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत बाढ़ से बचाव विषय पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संभावित आपदा की स्थिति में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों का मॉक ड्रिल भी कराया।कार्यक्रम में विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों सहित दर्जनों अभिभावकों ने भाग लिया।

भाजपा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन

अररिया (एजेंसी) : डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें स्मरण पर्व पर भाजपा जिला इकाई की ओर से शनिवार को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कुसियारगांव स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण झा ने किया,जबकि मंच संचालन जिला उपाध्यक्ष प्रताप नारायण मंडल ने किया।सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान, पूर्व विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव यादव तथा अररिया जिला प्रभारी विजय शंकर चौधरी उर्फ खोखा बाबू उपस्थित रहे।मौके पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह, पूर्व राष्ट्रीय परिषद सदस्य जयरानी यादव, नरपतगंज के पूर्व विधायक जयप्रकाश यादव, फारबिसगंज के पूर्व विधायक विद्यासागर केसरी, फारबिसगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण मेहता, सिकटी विधायक के प्रतिनिधि जोशी मंडल सहित भाजपा के जिला स्तर के अधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अपराध से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारा के लिये 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का किया जायेगा गठन: मुख्यमंत्री

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में सहयोग शिविर का किया जायेगा आयोजन

गया जी (एजेंसी) : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को गया जी मे 'नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के एकीकृत कार्यान्वयन पर आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) और बिहार न्यायिक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस सम्मेलन में राज्य में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से और समान रूप से लागू करने तथा न्याय वितरण प्रणाली में आपसी समन्वय मजबूत करने पर गहन चर्चा की जायेगी।मुख्यमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय सम्मेलन को बिहार के लिए ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि देश की लगभग 10 प्रतिशत आबादी और 14 करोड़ से अधिक लोगों को न्याय दिलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बिहार की न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन पर है। उन्होंने कहा कि बिहार की पहचान सदैव 'न्याय के साथ विकास' की रही है और नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी एवं जनहितकारी क्रियान्वयन इसी भावना को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि अपराध से जुड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिये 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जायेगा। हमलोग सहयोग कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें आवेदनकर्ता द्वारा समस्या को लेकर आवेदन दिया जाता है और उसका 30 दिनों के अंदर निष्पादन किया जाता है। प्रत्येक महीने के पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को सभी प्रखंडों में यह आयोजित किया जाता है। 30 दिनों में आवेदन का निष्पादन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को 31 वें दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से निलंबन का आदेश जाता है। प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को राज्य स्तर पर पटना में सहयोग शिविर का आयोजन किया जायेगा। इसमें वैसे लोग शामिल होंगे जिनके आवेदन का निष्पादन प्रखण्ड स्तर पर हुआ है लेकिन वे फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी समस्याओं का समाधान होगा और न्याय मिलेगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका सहयोगी बनेंगे तो काम अच्छा होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय तभी सार्थक होगा जब आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा। इसके लिए न्यायपालिका, पुलिस और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। सरकार और न्यायपालिका के बीच नियमित अंतराल पर समन्वय बैठकें आयोजित हों, ताकि जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ लागू करना समय की आवश्यकता है। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता है। अपराध नियंत्रण, निगरानी और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में आधुनिक तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार थानों को आधुनिक संसाधनों, सीसीटीवी, डिजिटल उपकरणों तथा वैज्ञानिक जांच व्यवस्था से सुसज्जित कर रही है। फॉरेंसिक लैब, मोबाइल फोरेंसिक वैन और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जिससे मामलों का शीघ्र निष्पादन संभव हो सके। 112 आपातकालीन सेवा के माध्यम से पुलिस औसतन 10 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच रही है, इसे घटाकर 7 से 8 मिनट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूलों और कॉलेजों के आसपास विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट तथा समयबद्ध न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। कानून का राज स्थापित करने के लिए किया गया निवेश आने वाले कई दशकों तक राज्य को लाभ पहुंचाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार शिक्षा और ज्ञान की ऐतिहासिक भूमि रही है। इसी माह राज्य में 211 नए डिग्री कॉलेज तथा 534 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ हो चुका है तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापन की दिशा में भी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों, आधुनिक तकनीक के समुचित उपयोग तथा नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से बिहार में कानून का राज और अधिक मजबूत होगा तथा राज्य विकास, समृद्धि और सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगा।

सम्मेलन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची, पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, बिहार न्यायिक अकादमी के चेयरमैन जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, बिहार के एडवोकेट जनरल सत्यदर्शी संजय, बिपार्ड के महानिदेशक डॉ० बी० राजेन्दर एवं गृह सचिव कुंदन कुमार ने भी संबोधित किया।

कार्यक्रम के दौरान बिपार्ड के महानिदेशक डॉ० बी० राजेन्दर ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत किया। सम्मेलन में शामिल डेलीगेट्स ने मुख्यमंत्री के साथ सामूहिक तस्वीर खिंचवाई।

सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, राज्य के विभिन्न जिलों के डिस्ट्रिक्ट जज, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्तागण, कानून विशेषज्ञ, मगध प्रमंडल की आयुक्त डॉ.सफीना एएन, गयाजी के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, वरीय पुलिस अधीक्षक गयाजी सुशील कुमार सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारीगण, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) तथा बिहार न्यायिक अकादमी से जुड़े अधिकारीगण थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के विभिन्न हिस्सों से प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा अन्य वरीय पदाधिकारी जुड़े थे।

मोदी सरकार की योजनाओं से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा विकास : डॉ. प्रेम कुमार

गया जी(एजेंसी) : बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है।सृजनी ऑडिटोरियम में भाजपा नेता एवं स्वदेशी विकास मंच के अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया।

अपने संबोधन में डॉ. कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब, किसान, महिला, युवा, मजदूर, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़े वर्ग, मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर उनके जीवन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया गया

है। डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए चार करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान कर रही है।

विकसित भारत के लिए सुशासन, रोजगार और सामाजिक समरसता जरूरी

डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर नल का जल पहुंचाने का कार्य तेजी से हुआ है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, जबकि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण तथा सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालयों के निर्माण से स्वच्छता के साथ महिलाओं की गरिमा को भी नई पहचान मिली है। वहीं डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी पहलों ने युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली को पारदर्शी व्यवस्था बताते हुए कहा कि इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि वहां की नई सरकार ने अपने शुरूआती निर्णयों और बजटीय प्रावधानों में महिला कल्याण, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, रोजगार सृजन, ग्रामीण सड़कों के विकास तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि जनता पारदर्शी, जवाबदेह और विकासोन्मुख शासन चाहती है तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वय से विकास की गति और तेज होगी।

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने विकसित भारत, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता और जनकल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निवेश, रोजगार, किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तीकरण के साथ लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति और मजबूत होगी तथा यही भारत के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी आधारशिला बनेगी। कार्यक्रम का नेतृत्व युवा सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कुमार ने किया।

टीबी मुक्त अभियान का आगाज, जिले में 10 हजार लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य

कटिहार, (एजेंसी) : जिले को क्षय रोग (टीबी) से पूरी तरह मुक्त करने के उद्देश्य से शनिवार को 'टीबी मुक्त अभियान, गाँव-गाँव, शहर-शहर' का भव्य शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने कोढ़ा प्रखंड के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोलासी से इस महाभियान का उद्घाटन किया। इसके तहत जिले की सभी पंचायतों में स्वास्थ्य मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से पूरे जिले में 10 हजार लोगों की टीबी स्क्रीनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस महाभियान का मुख्य उद्देश्य टीबी की शीघ्र पहचान, समय पर जांच और इलाज के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जिला स्वास्थ्य समिति के अनुसार, हर पंचायत में प्रतिदिन 40 लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। संदिग्ध रोगियों की पहचान कर उनका डेटा अनिवार्य रूप से निक्षय पोर्टल पर संधारित किया जाएगा। सबसे अहम पहल यह है कि जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले टीबी मरीजों को जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा उचित पोषण के लिए 'फूड-बास्केट' प्रदान किया जाएगा।

इन स्वास्थ्य मेगा कैंपों में आमजन को केवल टीबी की जांच ही नहीं, बल्कि एक ही छत के नीचे कई अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी सुलभ कराई जा रही हैं। इनमें गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, आवश्यक दवाइयों का वितरण, स्वास्थ्य परामर्श, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित टीकाकरण और परिवार कल्याण जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

जिले में बने माइक्रोप्लान के अनुरूप इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शिक्षा, शहरी विकास विभाग और जीविका का समन्वय स्थापित किया गया है। शनिवार को जिला स्तर के साथ-साथ प्रखंडों में बीडीओ, सीडीपीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इसका उद्घाटन किया गया। आशा, एएनएम और जीविका दीदियों के संयुक्त प्रयास से इस मेगा कैंप का सफलतापूर्वक शुभारंभ संपन्न हुआ।अभियान को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए इसकी कड़ी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। कटिहार जिलाधिकारी द्वारा प्रतिदिन शाम को जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और संबंधित कर्मियों के साथ अभियान की प्रखंडवार उपलब्धियों की गहन समीक्षा की जाएगी।

34 साल पुराना रामगोपाल यादव का अयोध्या पर भाषण फिर चर्चा में, राजनीतिक विवाद तेज

पटना (एजेंसी) : बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने चार साल के साधारण कारावास और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। चार साल की सजा होने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी संकट गहरा गया है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि अयोग्यता का सामना कर सकते हैं।यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित फार्महाउस में आयोजित नववर्ष समारोह का है। आरोप है कि जश्न के दौरान राजू कुमार सिंह ने लाइसेंसी पिस्तौल से हर्ष फायरिंग की, जिसकी गोली महिला वास्तुकार अर्चना गुप्ता को लग गई। गंभीर रूप से घायल अर्चना गुप्ता की बाद में मौत हो गई थी। अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या और शस्त्र अधिनियम से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया।सजा सुनाए जाने से पहले विधायक की ओर से अदालत से नरमी बरतने और परिवीक्षा का लाभ देने की मांग की गई थी। बचाव पक्ष का तर्क था कि घटना दुर्घटनावश हुई थी और हत्या की कोई मंशा नहीं थी। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि हर्ष फायरिंग जैसी घटनाएं गंभीर परिणाम पैदा करती हैं तथा ऐसे मामलों में कड़ा संदेश दिया जाना आवश्यक है। इस फैसले के बाद राजू कुमार सिंह के राजनीतिक भविष्य और उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

जनसुनवाई में उप-मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव एवं मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सुनीं आमजनों की समस्याएं

नीतीश कुमार की विकासोन्मुखी नीतियों को आगे बढ़ा रही एनडीए सरकार- बिजेंद्र प्रसाद यादव

बांकीपुर विधानसभा उप-चुनाव एनडीए की जीत शत-प्रतिशत सुनिश्चित- भगवान सिंह कुशवाहा

पटना, (एजेंसी) : जद (यू) के प्रदेश कार्यालय, पटना में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में बिहार के उप-मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव एवं मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने प्राप्त आवेदनों के विधिसम्मत एवं त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उप-मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि जिस प्रकार नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाता है, उसी प्रकार बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे पर भी टोल वसूली का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य सड़कों के बेहतर रख-रखाव एवं मेंटेनेंस के लिए आवश्यक रिवेन्यू जुटाना है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ह्यह्यन्याय के साथ विकासह्यह्य एवं ह्यह्यसबका साथ, सबका विकासह्यह्य के सिद्धांत पर कार्य करते हुए नीतीश कुमार की विकासोन्मुखी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून सबके लिए समान है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर हो, यदि वह कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने भरत तिवारी प्रकरण पर कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच आयोग अपना कार्य कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्य स्वतः सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के संबंध में श्री कुशवाहा ने कहा कि वहां एनडीए की जीत शत-प्रतिशत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर केवल सोशल मीडिया के नेता हैं और जमीनी स्तर पर उनका कोई जनाधार नहीं है।

संपादकीय

ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का 131 दिन बाद अंतिम संस्कार

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को शुरू हुए इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों को विदाई दी जा रही है। उनके पार्थिव शरीर को ताबूत में रखा गया है। लोगों को अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए 60 शहरों से होते हुए यह जनाजा उनके जन्म स्थान पर जाकर दफनाया जाएगा। सुप्रीम लीडर के परिवार में उनकी 14 महीने की पोती, उनकी पत्नी, बेटी और दामाद का भी जनाजा साथ में निकाला जा रहा है। सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर संयुक्त हवाई हमला किया था। इसमें उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के 131 दिन बाद 9 जुलाई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में दफनाया जाएगा। लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि मंडल तेहरान पहुंच गए हैं। इजराइल द्वारा धमकी दिए जाने के बाद उनके पुत्र मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं। इजराइल की धमकी के बाद अंतिम संस्कार के जनाजे की सुरक्षा एवं इसमें आने वाले करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का जनाजा 6 शहरों से होते हुए उनके जन्म स्थल पर ले जाया जाएगा जहां पर उनके पूर्वजों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया था, वहीं उन्हें भी दफन किया जाएगा। जनाजे में भारी भीड़ उमर रही है। सुरक्षा को देखते हुए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। तेहरान में विदेश से आने वालों के लिए ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ईरान के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए सैकड़ो सेवा केंद्र बनाए गए हैं। जहां पर लोगों के ठहरने खाने-पीने और स्वास्थ्य संबंधी इंतजाम किया गया है। ईरान की सरकार ने अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। यदि उन्होंने इस मौके पर कोई हरकत की तो इसका ऐसा जवाब दिया जाएगा जो अमेरिका और इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा। शुक्रवार से शुरू हुए जनाजे के इस कार्यक्रम में जिस तरह से ईरान की जनता उमड़ रही है वह सारी दुनिया के लोगों के लिए एक आश्चर्य में डालने की तरह है। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान के ऊपर हमला किया था उस समय ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। अमेरिकी शह में जो प्रदर्शन हो रहे थे, उसे देखते हुए अमेरिका को लग रहा था कि वह एक सप्ताह के अंदर ईरान में सत्ता परिवर्तन करा देगा।

मजबूत लोकतंत्र के लिये दागी नेताओं से मुक्ति जरूरी

भारतीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता के बाद अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति होने के साथ-साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। वर्ष 2047 तक ह्यविकसित भारतह्ण के लक्ष्य के साथ देश आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक नेतृत्व की नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। किंतु यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता अथवा तकनीकी विकास में नहीं, बल्कि उसकी राजनीति और शासन व्यवस्था की नैतिकता में निहित होती है। यदि लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखना है तो राजनीति को अपराध, भ्रष्टाचार और स्वार्थ की गिरफ्त से मुक्त करना ही होगा। आजादी के बाद से लगभग हर सरकार ने भ्रष्टाचार-मुक्त शासन, पारदर्शी प्रशासन और स्वच्छ राजनीति का वादा किया। अनेक आयोग बने, कानून बने और चुनाव सुधारों की चर्चाएं भी हुईं, लेकिन जब भी कोई ठोस एवं प्रभावी सुधार लागू करने का प्रयास हुआ, राजनीतिक दलों ने अपने-अपने हितों के अनुसार उसका समर्थन अथवा विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक शुचिता का प्रश्न आज भी अधूरा है। विडंबना यह है कि अब तक कोई ऐसा खाका सामने नहीं आ सका है, जिससे सिर्फ स्वच्छ छवि के लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिले। यह और बड़ी विडम्बना है कि जिस विषय पर पूरे राष्ट्र की सहमति होनी चाहिए, वही विषय राजनीतिक टकराव का माध्यम बन जाता है।

आए दिन संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद चुने गए जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता तो जताई जाती है, मगर उसके हल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती। संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है और इस संबंध में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी संदर्भ में भाजपा सरकार फिर से एक सौ तीसवें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को पाँच साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने और लगातार तीस दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। अगर विधेयक की जांच के बाद संयुक्त संसदीय समिति इसे अपनी मंजूरी दे देती है, तो संसद के मानसून सत्र में इस पर बहस की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने की आशंका के मद्देनजर समिति का बहिष्कार कर दिया था।

निश्चित ही संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। यदि कोई जनप्रतिनिधि हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद अथवा संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में है, तो क्या वह जनता का प्रतिनिधित्व करने का नैतिक अधिकार बनाए रखता है? यह प्रश्न केवल कानूनी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हालांकि इस प्रकार के कानून पर कई संवैधानिक प्रश्न भी उठते हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को तब तक निर्दोष मानता है जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए। केवल आरोप के आधार पर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाना राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार भी बन सकता है। विपक्षी दलों की यह आशंका पूरी तरह निराधार नहीं कही जा सकती कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं होंगे तो सत्ता में बैठी सरकारें विरोधियों के विरुद्ध जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकती हैं। इसलिए किसी भी नए कानून में प्राकृतिक न्याय, न्यायिक समीक्षा और निष्पक्ष जांच की सुदृढ़ व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन इन आशंकाओं के कारण सुधार की पूरी प्रक्रिया को रोक देना भी उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में सुधार का अर्थ किसी दल को लाभ या हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करना है। यदि कानून संतुलित, पारदर्शी और न्यायसंगत हो तो वह लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि अधिक विश्वसनीय बनाता है।

भारत की राजनीति में अनेक ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक मयार्दाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए। बिहार में लालू प्रसाद यादव से लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तथा उनके कुछ मंत्रियों तक, विभिन्न राजनीतिक दलों के अनेक नेता ऐसे रहे हैं जो गंभीर आरोपों अथवा जेल में रहने के बावजूद सत्ता पर बने रहने का प्रयास करते रहे। यह किसी एक दल का प्रश्न नहीं है, लगभग सभी बड़े राजनीतिक दल समय-समय पर इस आलोचना के घेरे में रहे हैं। जेल से सरकार चलाने अथवा संवैधानिक पद पर बने रहने की मानसिकता लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं कही जा सकती। यह सही है कि कानून अपना कार्य करेगा और न्यायालय अंतिम निर्णय देगा, किंतु सार्वजनिक जीवन केवल कानूनी वैधता से नहीं चलता, उसका आधार नैतिक वैधता भी होती है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि केवल अधिकारों का नहीं, बल्कि आदर्शों का भी प्रतीक होता है। यदि उसके ऊपर गंभीर आरोप हों और वह फिर भी पद से चिपका रहे, तो जनता का लोकतांत्रिक विश्वास कमजोर पड़ता है। राजनीति में पद त्यागना पराजय नहीं, बल्कि नैतिक साहस का परिचायक होता है।

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें आर्थिक प्रगति के साथ सुशासन, डिजिटल पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन और जनभागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, एक्सप्रेस-वे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तेज आर्थिक विकास से नहीं बनेगा, वह तभी बनेगा जब शासन चलाने वाले व्यक्तियों की विश्वसनीयता भी उतनी ही मजबूत होगी। विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र की राजनीति भी विश्व के लिए आदर्श बननी चाहिए। आज आवश्यकता केवल कानून बदलने की नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति बदलने की भी है। राजनीतिक दलों को चुनावी टिकट देते समय उम्मीदवार के चरित्र, सार्वजनिक जीवन, सामाजिक सेवा और नैतिक छवि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय कई बार राजनीतिक दलों से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण सार्वजनिक करने को कह चुका है, किंतु व्यवहार में इसमें अपेक्षित परिवर्तन दिखाई नहीं देता। यदि राजनीतिक दल स्वयं आत्मानुशासन नहीं अपनाएंगे, तो केवल कानून से समस्या का समाधान संभव नहीं होगा।

इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में भी व्यापक सुधार अपेक्षित हैं। जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का वर्षों तक लंबित रहना लोकतंत्र के लिए घातक है। विशेष न्यायालयों द्वारा समयबद्ध सुनवाई, निष्पक्ष जांच और शीघ्र निर्णय की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि न निर्दोष व्यक्ति वर्षों तक संदेह के घेरे में रहे और न दोषी व्यक्ति कानून की तकनीकी जटिलताओं का लाभ उठाकर जनता का प्रतिनिधित्व करता रहे। लोकतंत्र की सफलता केवल संविधान से नहीं, बल्कि राजनीतिक चरित्र से सुनिश्चित होती है। जब तक राजनीति में नैतिकता, सेवा, त्याग और उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक भ्रष्टाचार और अपराध का दुष्चक्र पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, किंतु राष्ट्रीय हित से जुड़े सुधारों का विरोध केवल राजनीतिक लाभ-हानि के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रस्ताव में कमियां हैं तो उन्हें सुधारने के सुझाव दिए जाएं, लेकिन सुधार की दिशा को अवरुद्ध करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिचायक नहीं माना जा सकता।

आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु भारत का स्वप्न है, तो दूसरी ओर राजनीति की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने की चुनौती भी है। इन दोनों लक्ष्यों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। आर्थिक विकास और नैतिक विकास समानांतर चलेंगे तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। समय की पुकार है कि सत्ता और विपक्ष दोनों दल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर लोकतंत्र की पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। देश की राजनीति को आपराधिक छवि के लोगों से मुक्त करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए जो कानून बने, उसमें अपराधों की प्रकृति स्पष्ट किए जाने से लेकर ऐसे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है, ताकि महज बदले या किसी सरकार को अस्थिर करने की मंशा से इसका दुरुपयोग न हो सके।

ललित गर्ग

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

यदि आप वही करते हैं, जो आप हमेशा से करते आये हैं तो आपको वही मिलेगा, जो हमेशा से मिलता आया है।

:टोनी रॉबिंस

एक चीज मैंने देखी है जब आप प्यार करते है दर्द की सीमा तक तो वो दर्द नहीं रहता बस प्यार बढ़ता जाता है।

:मदर टेरेसा

क्षणिक वैराग्य का भ्रम और आदमी का मसानिया सच

मनुष्य जितना आधुनिक होता जा रहा है, उतना ही भीतर से विरोधाभासों का शिकार भी होता जा रहा है। ज्ञान, नैतिकता, संस्कार और वैराग्य पर लंबे लंबे भाषण देना आज आसान हो गया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उतारना पहले से कहीं अधिक कठिन प्रतीत होता है। यही कारण है कि आज समाज में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो दूसरों को जीवन जीने की सीख तो बड़े आत्मविश्वास से देते हैं, लेकिन स्वयं उसी कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते। हर व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी और विवेकशील मानता है, लेकिन अपने से अधिक बुद्धिमान किसी दूसरे को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। विडंबना यह है कि व्यक्ति स्वयं चाहे झूठ बोले या झूठ के सहारे जीवन बिताए, लेकिन दूसरों से हमेशा सत्य की अपेक्षा रखता है। शायद इसी सत्य को हमारे पूर्वजों ने वर्षों पहले एक पंक्ति में समेट दिया था ₹पर उपदेश कुशल बहुतेरे।

आज का मनुष्य स्वयं को सबसे अधिक समझदार और अनुभवी मानता है। उसे अपने दोष दिखाई नहीं देते, लेकिन दूसरों की छोटी सी भूल भी बड़ी नजर आती है। स्वयं झूठ और स्वार्थ से समझौता कर लेने वाला व्यक्ति भी दूसरों से ईमानदारी और आदर्शवाद की अपेक्षा करता है। यही हमारे समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। वर्तमान समाज में ज्ञान का प्रदर्शन बढ़ा है, लेकिन आत्ममंथन कम हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक बैठकों तक हर कोई जीवन दर्शन, अध्यात्म और मानवीय मूल्यों पर उपदेश देता दिखाई देता है। आज के व्यक्ति की एक और विशेषता यह है कि उसे अपने घर परिवार से अधिक संसार भर का ज्ञान रहता है और वह अपने इस तथाकथित ज्ञान का प्रदर्शन भी पूरे आत्मविश्वास के साथ करता रहता है। वह वैराग्य, अध्यात्म और जीवन दर्शन पर ऐसी ऐसी बातें करता है कि क्षणभर के लिए लगता है मानो कोई महापुरुष हमारे सामने बैठा हो। किंतु परिस्थितियां बदलते ही वही व्यक्ति अपने सारे आदर्श भूल जाता है। उस₹का वैराग्य स्थायी नहीं, बल्कि परिस्थितिजन्य होता है।

यदि सच कहा जाए तो आज अधिकांश व्यक्ति 'मसानिया वैराग्य' का शिकार है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर एकत्रित लोगों की बातें ध्यान से सुनिए। उस समय वैराग्य और जीवन दर्शन की गंगा बहती हुई प्रतीत होती है। लोग कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सभी से प्रेमपूर्वक मिल-जुलकर रहना चाहिए। धन के पीछे अंधी दौड़ नहीं लगानी चाहिए और पैसे के कारण रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पैसा जीवन में सब कुछ नहीं होता, प्रेम, अपनापन और व्यवहार ही जीवन की वास्तविक पूंजी हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि अब सभी लोग अपने जीवन की दिशा बदल देंगे। लेकिन यही वैराग्य अधिक देर तक टिक नहीं पाता। मृतक की चिता की अग्नि शांत होने से पहले ही लोगों की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। कपाल क्रिया पूरी होने से पहले ही मोबाइल फोन बजने लगते हैं, व्यापार की बातें शुरू हो जाती हैं, राजनीति पर चर्चा होने लगती है और जीवन फिर उसी गति से स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और मोह माया की ओर लौट पड़ता है। यही वह क्षण है, जहां तथाकथित वैराग्य का वास्तविक चेहरा सामने आ जाता है।

आज रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि संवेदनाएं भी औपचारिकता बनती जा रही हैं। जीवित व्यक्ति के लिए समय निकालना कठिन लगता है, लेकिन उसके निधन पर सामाजिक उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक समझा जाता है। कई लोग अंतिम यात्रा में भी इसलिए शामिल होते हैं कि समाज उन्हें संवेदनशील समझे। दुख की अभिव्यक्ति भी अब कई बार हृदय से अधिक सामाजिक दायित्व का निर्वहन बनकर रह गई है। यदि मृत आत्मा सब कुछ देख रही हो, तो शायद वह भी यही पूछे जिन लोगों का प्रेम आज उमड़ रहा है, वे मेरे जीवित रहते कहां थे? वास्तव में समस्या मृत्यु नहीं, बल्कि हमारी स्मृति की अल्पायु है। श्मशान हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाता है, लेकिन हम उस सत्य को घर लौटते-लौटते भूल जाते हैं। इसलिए हमारा वैराग्य शाश्वत नहीं, केवल ₹मसानिया वैराग्य₹ बनकर रह जाता है ऐसा वैराग्य जो चिता की लपटों के साथ जन्म लेता है और राख ठंडी होते ही समाप्त हो जाता है।

जीवन का वास्तविक वैराग्य श्मशान में नहीं, बल्कि व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि हम सचमुच यह मानते हैं कि जीवन अनिश्चित है, तो हमें अपने रिश्तों में प्रेम बढ़ाना होगा, अहंकार कम करना होगा, क्षमा करना सीखना होगा और धन को साधन मानना होगा, साध्य नहीं। मृत्यु का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अंततः मनुष्य अपने साथ न धन ले जाता है, न पद और न प्रतिष्ठा; वह पीछे छोड़ जाता है तो केवल अपने व्यवहार की स्मृतियां। यदि श्मशान से लौटते समय हम अपने भीतर थोड़ा-सा भी स्थायी परिवर्तन लेकर लौटें, तभी उस वैराग्य का अर्थ है। अन्यथा चिता की अग्नि की तरह हमारा वैराग्य भी कुछ देर धधक कर राख हो जाएगा और हम फिर उसी मोह, माया और दिखावे की दुनिया में खो जाएंगे। यही आधुनिक मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और समाज की सबसे गंभीर विडंबना है।

अरविंद रावल

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

सूडोकु नवताल- 7563

मध्यम

			1					6
7		2		5				9
		4			2	7	5	
5	7				9		1	8
				6				
6	1		3				2	4
	5	1	9			8		
2				8		9		1
9					3			

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7562 का हल

1	9	3	2	4	6	5	8	7
4	7	2	5	1	8	3	6	9
6	5	8	7	3	9	1	2	4
3	8	9	4	5	1	2	7	6
2	4	7	6	9	3	8	1	5
5	1	6	8	7	2	4	9	3
8	2	4	9	6	5	7	3	1
7	6	1	3	2	4	9	5	8
9	3	5	1	8	7	6	4	2

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शिक्षा दर्शन का आधार मैकाले की औपनिवेशिक दासता का प्रतिकार

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शिक्षा दर्शन मात्र अक्षर ज्ञान अथवा व्यावसायिक कुशलता तक सीमित नहीं था, अपितु वह मनुष्य के भीतर छिपी देवत्व की शक्ति को जाग्रत करने और उसे राष्ट्र-चेतना से जोड़ने का एक महती अनुष्ठान था। भारतीय वांग्मय में शिक्षा का परम लक्ष्य मोक्ष और चेतना का विस्तार माना गया है-

सा विद्या या विमुक्तये।

अर्थात- विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे। किंतु ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति का एकमात्र ध्येय ऐसे मानसिक दासों का निर्माण करना था, जो रंग- रूप में तो भारतीय हों परंतु अपनी आत्मा, संस्कृति और चिंतन में पूर्णतः ब्रिटिश हो जाएं। डॉ. मुखर्जी भारत के उन गिने-चुने मनीषियों में अग्रणी थे, जिन्होंने इस सांस्कृतिक आक्रमण को अत्यंत सूक्ष्मता से समझा। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत अपनी शिक्षा पद्धति का भारतीयकरण नहीं करेगा, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी देश मानसिक रूप से परतंत्र ही रहेगा। वर्ष 1934 में मात्र 33 वर्ष की युवावस्था में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार ग्रहण करना डॉ. मुखर्जी के असाधारण बौद्धिक सामर्थ्य का परिचायक था। इस सर्वोच्च पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा के व्यावहारिक और राष्ट्रीय स्वरूप की एक नई रूपरेखा देश के सम्मुख रखी। प्राचीन ग्रंथों में शिक्षा के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सहजता को सर्वोपरि माना गया है। डॉ. मुखर्जी का स्पष्ट मत था कि कोई भी राष्ट्र अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करके वैश्विक स्तर पर महान नहीं बन सकता। उन्होंने विश्वविद्यालय के इतिहास में प्रथम बार भारतीय भाषाओं, विशेषकर बांग्ला को उच्च शिक्षा और परीक्षा का माध्यम बनाने की नीति लागू की। वर्ष 19 37 के दीक्षांत समारोह में उन्होंने गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर को आमंत्रित किया, जिन्होंने इतिहास में पहली बार संपूर्ण दीक्षांत भाषण अंग्रेजी के स्थान पर मातृभाषा बांग्ला में दिया। यह मैकाले के उस मिथक पर करारा प्रहार था कि भारतीय भाषाएँ उच्च विज्ञान और दर्शन की अभिव्यक्ति में अक्षम हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और चरक-सुश्रुत संहिताओं के संदर्भों का अध्ययन कर डॉ. मुखर्जी ने यह प्रतिपादित किया कि भारत का प्राचीन विज्ञान अत्यंत समृद्ध था। उन्होंने विश्वविद्यालय में कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मध्य के कृत्रिम विभाजन को समाप्त किया। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों से जोड़ने के लिए विशेष पीठ और शोध केंद्रों की स्थापना की।

डॉ. मुखर्जी के शिक्षा संबंधी दर्शन को तीन प्रमुख वैचारिक अधिष्ठानों के अंतर्गत समझा जा सकता है. जो सीधे हमारे सनातन ग्रंथों से प्रेरित हैं- चरित्र निर्माण, ज्ञान-विज्ञान का समन्वय और अन्त्योदय एवं सुलभता, जो क्रमशः मनुस्मृति एवं उपनिषद, भगवद्गीता एवं सांख्य दर्शन और ऋग्वेद के सूत्र पर आधारित हैं। मनु महाराज मनुस्मृति में उद्घोष करते हुए कहते हैं-

न केवलं यशांसि प्राप्नोति, अपितु चरित्रं रक्षति।

अर्थात- केवल यश प्राप्त करना शिक्षा नहीं, चरित्र की रक्षा करना ही वास्तविक शिक्षा है।

डॉ. मुखर्जी का मानना था कि यदि शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील, अनुशासित और राष्ट्रभक्त नहीं बनाती, तो वह समाज के लिए एक घातक अस्त्र सिद्ध हो सकती है। वे विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में नीतिशास्त्र और भारतीय दर्शन के समावेश के प्रबल पक्षधर थे। मुंडकोपनिषद में दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है- परा अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान और अपरा अर्थात लौकिक या व्यावहारिक विज्ञान। डॉ. मुखर्जी ने इस शाश्वत सत्य को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ढाला। उनका विचार था कि आधुनिक भारत को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जिनके हाथों में आधुनिकतम तकनीक और विज्ञान हो, किंतु जिनका हृदय उपनिषदों और गीता के शाश्वत जीवन-मूल्यों से स्पंदित हो। ऋग्वेद का मंत्र है-

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः।

अर्थात- सभी को समान रूप से संसाधन और ज्ञान प्राप्त हो।

डॉ. मुखर्जी शिक्षा को किसी विशिष्ट वर्ग या संभ्रांत समाज की जागीर नहीं बनने देना चाहते थे। उन्होंने निर्धन और वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की और सायंकालीन कक्षाओं की शुरूआत की, ताकि कामकाजी युवा भी उच्च शिक्षा से वंचित न रहें।

मंत्रिमंडल में रहते हुए और स्वतंत्र भारत की संसद में एक प्रखर विपक्षी नेता के रूप में, उन्होंने तत्कालीन नेहरू सरकार की शिक्षा नीतियों की विसंगतियों पर निरंतर रचनात्मक प्रहार किए। उनके विचार आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वैचारिक मूलाधार प्रतीत होते हैं। वे पाठ्यपुस्तकों से उन सभी विवरणों को हटाने के पक्ष में थे, जो भारतीयों में हीनभावना ग्रसित करते थे और आक्रांताओं का महिमामंडन करते थे। वे औपनिवेशिक प्रतीकों का पूर्णत विलोपन चाहते थे। शारीरिक एवं सैनिक शिक्षा का अनिवार्य समावेश चाहते थे। स्वामी विवेकानंद के ₹लोहे की मांसपेशियाँ और फौलाद के स्नायु₹ के सिद्धांत से प्रेरित होकर उन्होंने युवाओं के लिए शारीरिक सौष्ठव और आत्मरक्षा के प्रशिक्षण को अकादमिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने पर बल दिया। उनका दृढ़ मत था कि शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को राजनीतिक हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त रहना चाहिए। शिक्षाविदों और कुलपतियों की नियुक्ति का आधार केवल और केवल योग्यता और विद्वत्ता होनी चाहिए, न कि राजनीतिक निष्ठा।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनीतिक योद्धा या कश्मीर के मुक्तिदाता ही नहीं थे, वरन वे मूलतः एक द्रष्टा शिक्षाविद थे। आज जब देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को औपनिवेशिक बेड़ियों से मुक्त कर अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास कर रहा है, तब डॉ. मुखर्जी का शिक्षा दर्शन एक ध्रुवतारे की भांति हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। उनका जीवन इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जब उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता का समन्वय होता है, तभी देश को डॉ. मुखर्जी जैसा सभ्यतागत महानायक प्राप्त होता है, जो राष्ट्र की प्रादेशिक और वैचारिक सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने से तनिक भी पीछे नहीं हटता।

अशोक प्रवृद्ध

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

दैनिक पंचांग

5 जुलाई 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति
सूर्य	मिथुन में
चंद्र	कुंभ में
मंगल	वृष में
बुध	मिथुन में
गुरु	कर्क में
शुक्र	सिंह में
शनि	मीन में
राहु	कुंभ में
केतु	सिंह में

राहुकाल 4.30 से 6.00 बजे तक

लग्नारंभ समय	
कर्क	06.14 बजे से
सिंह	08.30 बजे से
कन्या	10.42 बजे से
तुला	12.53 बजे से
वृश्चिक	15.07 ब.से
धनु	17.23 बजे से
मकर	19.29 बजे से
कुंभ	21.15 बजे से
मीन	22.48 बजे से
मेष	00.18 बजे से
वृष	01.58 बजे से
मिथुन	03.57 बजे से

रविवार 2026 वर्ष का 186 वा दिन
दिशाशूल पश्चिम **ऋतु** वर्षा।
विक्रम संवत् 2083 **शक संवत्** 1948
मास आषाढ़ (दक्षिण भारत में ज्येष्ठ)
पक्ष कृष्ण
तिथि पंचमी 13.31 बजे को समाप्त।
नक्षत्र शतभिषा 15.13 बजे को समाप्त।
योग आयुष्मान 16.40 बजे को समाप्त।
करण तैतिल 13.31 बजे तदनन्तर गर 01.44 बजे रात्र को समाप्त।
चन्द्रायु 19.9 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 22° 48'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1872761
जूलियन दिन 2461226.5
कलियुग संवत् 5128
कल्पारंभ संवत् 1972949128
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885128
वीरनिर्वाण संवत् 2552
हिजरी सन् 1448
महीना मोहर्रम
तारीख 19

दिन का चौघड़िया				रात का चौघड़िया			
उद्वेग	05.56 से	07.23 बजे तक		शुभ	05.36 से	07.09 बजे तक	
चर	07.23 से	08.51 बजे तक		अमृत	07.09 से	08.41 बजे तक	
लाभ	08.51 से	10.18 बजे तक		चर	08.41 से	10.14 बजे तक	
अमृत	10.18 से	11.46 बजे तक		रोग	10.14 से	11.46 बजे तक	
काल	11.46 से	01.14 बजे तक		काल	11.46 से	01.19 बजे तक	
शुभ	01.14 से	02.41 बजे तक		लाभ	01.19 से	02.51 बजे तक	
रोग	02.41 से	04.09 बजे तक		उद्वेग	02.51 से	04.24 बजे तक	
उद्वेग	04.09 से	05.36 बजे तक		शुभ	04.24 से	05.53 बजे तक	

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

संक्षिप्त समाचार

चीनी मॉडल से नहीं, नेपाल का विकास नेपाली मॉडल से ही संभवः ज्ञानेंद्र शाही

काठमांडू। नेपाल के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) के संसदीय दल के नेता ज्ञानेंद्र शाही ने चीनी दूतावास से जुड़े एक कार्यक्रम में दो टूक कहा है कि नेपाल के विकास के लिए किसी भी विदेशी मॉडल की नकल नहीं की जानी चाहिए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आयोजित 'चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 105 वर्षः ऐतिहासिक अनुभव और नेपाल का विकास' विषयक विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास बाहर से आयात करने का विषय नहीं है। शाही ने ज़ोर देकर कहा कि नेपाल के भौगोलिक और सामाजिक परिवेश में अन्य देशों में सफल हुए विकास के मॉडल को हूबहू लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नेपाल को अपनी मिट्टी और जमीनी हकीकत पर आधारित मौलिक मार्ग अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर नेपाल को अपना खुद का विकास मार्ग तैयार करना होगा। शाही ने कहा कि नेपाल की मुख्य समस्या संभावनाओं की कमी नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने की कमजोरी है। शाही ने कहा, "विकास बाहर से आयात की जाने वाली चीज़ नहीं है और न ही किसी दूसरे देश के विकास मॉडल की हूबहू नकल करके सफलता हासिल की जा सकती है। एक देश में सफल हुआ विकास मॉडल हिमालय की गोद में बसे नेपाल में जस का तस लागू नहीं हो सकता।" उन्होंने कहा कि नेपाल प्राकृतिक संपदा, अपार जलस्रोत और दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (भारत और चीन) के बीच स्थित रणनीतिक भौगोलिक स्थिति से संपन्न राष्ट्र है, लेकिन क्रियान्वयन पक्ष कमजोर होने के कारण देश पिछड़ गया है। नेपाल-चीन संबंधों पर ज्ञानेंद्र शाही ने कहा कि दोनों देशों के बीच का रिश्ता पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता, भौगोलिक अखंडता के सम्मान और एक-दूसरे के मामलों में अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और स्थिर नेपाल ही इस पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता का सबसे मजबूत आधार होगा।

नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत बनाने को चीन के राजदूत ने पेश किए चार सूत्री प्रस्ताव

काठमांडू। चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने नेपाल के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए चार सूत्री प्रस्ताव रखा है। झांग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के 105वें स्थापना दिवस पर शनिवार को काठमांडू में आयोजित विचार गोष्ठी में यह पेश किया। राजदूत झांग ने नेपाल-चीन संबंधों के भविष्य के संदर्भ में बोलते हुए दोनों देशों के राजनीतिक दलों के बीच गरीबी निवारण, आर्थिक विकास और पार्टी निर्माण के अच्छे अभ्यासों को साझा करने का पहला प्रस्ताव रखा। उसी तरह, नेपाल की विकास रणनीति के साथ बीआरआई को जोड़ते हुए 'ट्रान्स-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क' के निर्माण को तीव्रता देने का उनका दूसरा प्रस्ताव है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर समन्वय करते हुए राष्ट्रपति सी जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिविलाइजेशन और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के कार्यान्वयन में मिलकर कार्य करने के प्रति प्रतिबद्धता भी जताई। युवा पीढ़ी के बीच भ्रमण और सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालित कर नेपाल-चीन मैत्री संबंध को हस्तांतरित करने का उनका चौथा प्रस्ताव है। पार्टी की सफलता और विशेषता के बारे में चर्चा करते हुए राजदूत झांग ने कहा कि सीपीसी विश्व की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी है। इस पार्टी में 10 करोड़ 12 लाख से अधिक सदस्य हैं। उन्होंने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि विश्व शांति को बढ़ावा देने और मानव प्रगति की यात्रा में योगदान देने के लिए चीन सदैव तैयार है।

राजौरी में एलओसी के पास गश्त के दौरान माइन ब्लास्ट में भारतीय सेना के नायब सूबेदार घायल

राजौरी। राजौरी जिले के नौशहरा के झांगड़ सेक्टर में एलओसी के पास गश्त के दौरान माइन ब्लास्ट में भारतीय सेना की 14 असम यूनिट के नायब सूबेदार हितेश्वर गोगोई घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कमांड अस्पताल उधमपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार सेना की टीम झांगड़ के अग्रिम इलाके में नियमित पेट्रोलिंग और क्षेत्र की निगरानी कर रही थी। इसी दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। इसमें नायब सूबेदार हितेश्वर घायल हो गए। विस्फोट के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और सेना ने तत्काल पूरे क्षेत्र को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि घायल अधिकारी को पहले नजदीकी सैन्य चिकित्सा केंद्र पहुंचाया गया, जहां से कमांड अस्पताल उधमपुर भेजा गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक यह विस्फोट पुराने लैंडमाइन या गश्त मार्ग में मौजूद विस्फोटक सामग्री के कारण हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके की जांच कर रही हैं ताकि किसी अन्य संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। उल्लेखनीय है कि नियंत्रण रेखा से सटे राजौरी और नौशहरा सेक्टर में बारिश के मौसम में कई बार पुरानी बारूदी सुरंगें खिसक जाती हैं। इससे जवानों के लिए खतरा बढ़ जाता है।

चुनाव आयोग ने के. कविता को पार्टी का नाम बदलने का दिया निर्देश, 15 दिन में तीन नए नाम सुझाने को कहा

हैदराबाद। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने के. कविता को उनकी नई राजनीतिक पार्टी तेलंगाना रक्षण सेना (टीआरएस) का नाम बदलने का निर्देश दिया है। विभिन्न हितधारकों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों के बाद आयोग ने यह कदम उठाया है। निर्वाचन आयोग ने के. कविता को भेजे गए पत्र में 15 दिनों के भीतर पार्टी के लिए तीन वैकल्पिक नाम प्रस्तावित करने को कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो पार्टी के पंजीकरण के लिए किया गया आवेदन बिना किसी अतिरिक्त सूचना के खारिज किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि के. कविता ने 25 अप्रैल को मेडचल में अपने नए राजनीतिक संगठन की शुरुआत की थी। प्रारंभ में पार्टी का नाम 'तेलंगाना राष्ट्र सेना' रखा गया था, लेकिन तीन दिन बाद 28 अप्रैल को इसे बदलकर 'तेलंगाना रक्षण सेना' कर दिया गया। पार्टी के गठन से पहले फरवरी में कविता ने निर्वाचन आयोग को पांच संभावित नामों का प्रस्ताव भेजा था। इनमें तेलंगाना प्रजा जागृति, तेलंगाना जागृति, तेलंगाना रक्षण सेना, तेलंगाना राष्ट्र जागृति और तेलंगाना प्रजा शक्ति शामिल थे। इनमें से उन्होंने अंततः 'तेलंगाना रक्षण सेना' नाम को चुना। निर्वाचन आयोग ने प्रारंभिक स्तर पर इस नाम को सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित करने की अनुमति दी थी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि अंतिम मंजूरी निर्धारित अवधि में प्राप्त होने वाली आपत्तियों और उनके निस्तारण के बाद ही दी जाएगी।

अब चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी छोड़ा ममता का साथ

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी और उसकी विभिन्न इकाइयों के बैंक खातों की हस्ताक्षरकर्ता तथा निर्वाचन आयोग के समक्ष पार्टी का प्रतिनिधित्व करने सहित सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से भी स्वयं को मुक्त करने का अनुरोध किया है।

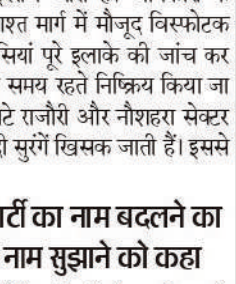

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, चंद्रिमा भट्टाचार्य के पुत्र सौरभ बसु के हाल ही में ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल के बागी गुट में शामिल होने के बाद से ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। इसी घटनाक्रम के बीच उनके इस्तीफे ने पार्टी की अंदरूनी स्थिति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें किसी व्यक्ति या नेता से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ परिस्थितियों के कारण उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं और इसी वजह से उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि वह आगे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में बनी रहेंगी या नहीं।

एथेनॉल के विरोध पर सरकार बोली- यह जांची-परखी साइंटिफिक प्रोसेस

इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई, टॉप एजेंसियां भी टेस्ट कर चुकीं

एजेंसी, नई दिल्ली

पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर हो रहे विरोध के बीच शनिवार को सरकार ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों-रात नहीं हुआ। यह एक जांची-परखी, साइंटिफिक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस है। इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई है और टॉप एजेंसियां भी इसका टेस्ट कर चुकीं हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर दिल्ली में हुई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट वर्तिका शुक्ला ने यह बात कही। वर्तिका शुक्ला ने बताया कि देश में साल 2013 और 2014 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था। अब इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) की जा रही है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय से पांच साल पहले यानी दिसंबर 2025 तक ही पूरा कर लिया गया है।

भारत में क्यों हो रहा है E20 पेट्रोल का विरोध?: भारत में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के इस मिश्रण यानी E20-पेट्रोल का विरोध हो रहा है। खासकर 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक परेशान हैं। उनका दावा है कि इस फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया और इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं। हालांकि, भारत सरकार का कहना है कि एथेनॉल से माइलेज में मामूली कमी जरूर आती है, लेकिन इससे गाड़ी का पिकअप और इंजन परफॉर्मेंस बेहतर होता है।

टॉप एजेंसियां इसकी टेस्टिंग कर चुकीं: एक्सपर्ट शुक्ला ने बताया कि विशेष रूप से साल 2018 में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) को एक स्ट्रक्चर्ड यानी व्यवस्थित तरीके से सभी स्टेकहोल्डर्स के सामने चर्चा और विचार-विमर्श के लिए रखा गया था। यह पूरा प्रोग्राम साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स और उन्हें सपोर्ट करने वाली मुख्य एजेंसियों का पूरा सपोर्ट है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) और सियाम जैसी टॉप एजेंसियां इसकी बड़े लेवल पर टेस्टिंग कर चुकी हैं। वर्तिका शुक्ला के अनुसार, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का यह प्रोग्राम दुनिया भर में अपनाई जाने वाली ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बिल्कुल अनुरूप है। इसके जरिए फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को 'ग्रीन' बनाया जा रहा है, ताकि पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सके।

आतंकियों व अलगाववादियों के महिमामंडन वाली पुस्तक पर तत्काल रोक की मांग

एजेंसी, जम्मू

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने शनिवार को सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में वितरित एक विवादित पुस्तक पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। उन्होंने शिक्षा विभाग पर राष्ट्र विरोधी सामग्री को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए संबंधित पुस्तक को मंजूरी दिए जाने और उसे वितरित करने की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि पैराडाइज़ पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किताब 'पर्सनैलिटीज़ एंड लेजेंड्स ऑफ़ जेएंडके' अलगाववादियों, आतंकवादियों और पत्थरबाज़ों का महिमामंडन कर भारत को नकारात्मक रूप में दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इसे युवा मस्तिष्क को प्रभावित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है जो युवाओं को शैक्षणिक भटकाव की तरफ ले जाएगा। शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में भेजे जाने से पहले शिक्षा विभाग की तरफ से गठित समिति ने इस किताब को मंजूरी दी थी।उन्होंने कहा कि संबंधित पुस्तक पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही इसे मंजूरी देने, प्रकाशित करने और वितरण के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाने की मांग करते हुए कहा कि विभाग ने सरकारी स्कूलों में किताब को अनुमति देकर "गंभीर चूक" की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन के दौरान लिए गए फैसलों का ज़िक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि पहले भी ऐसी ही सामग्री वाली लगभग 25 किताबों को वापस ले लिया गया था या उन पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने सरकार से इस मामले में भी वैसा ही रुख अपनाने का आग्रह किया।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए शर्मा ने आरोप लगाया कि यह प्रकाशन आतंकवाद से जुड़े मामलों में दोषी या आरोपित व्यक्तियों को "शहीद" बताता है, जबकि सुरक्षाकर्मियों के बलिदान को नज़रअंदाज़ करता है। शर्मा ने जम्मू-कश्मीर सरकार और जांच एजेंसियों से आग्रह किया कि बिना देरी किए मामले की जांच करें और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करें।

डिजिटल अरेस्ट मामले में मप्र के मुरैना से दो चचेरे भाई गिरफ्तार

एजेंसी, भोपाल/ग्वालियर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में सेवानिवृत्त महिला स्वास्थ्य कर्मचारी से 1.58 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुरैना के पोरसा से दो चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह के तार अंतरराष्ट्रीय चाइनीज नेटवर्क से जुड़े हैं, जो ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में तब्दील कर विदेश भेजते थे। साइबर पुलिस के अनुसार दोनों चचेरे भाइयों की गिरफ्तारी शुक्रवार रात हुई। ठगी का यह सनसनीखेज मामला ग्वालियर के जनकगंज इलाके का है, यहां की निवासी रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन मीनाक्षी नाखरे को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया।

ठगों ने खुद को सीबीआई और ईडी का आला अधिकारी बताते हुए उन्हें वीडियो कॉल के जरिए 'डिजिटल हाउस अरेस्ट' कर लिया था। आरोपितों ने महिला को मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे

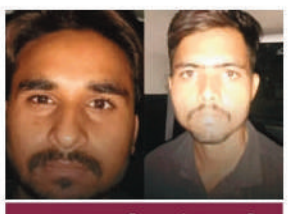

अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े ठगी के तार

केस में फंसाने और जेल भेजने का ऐसा खौफ दिखाया कि उन्होंने डर के मारे अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी और अलग-अलग बैंकों की एफडी तुड़वाकर कथित जांच के नाम पर 1.58 करोड़ रुपये ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए।

साइबर पुलिस ने जब इस बड़ी रकम के ट्रांजेक्शन और बैंक खातों की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, तो ठगी के 4 लाख रुपये मुरैना के पोरसा निवासी राहुल तोमर के खाते में ट्रांसफर होने की बात सामने आई।

चंपत राय के बचाव में उतरे अयोध्या के संत ट्रस्ट से इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की अपील

एजेंसी, अयोध्या

श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (ट्रस्ट) के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अयोध्या संत मंडल उनके समर्थन में उतर आया है। संतों ने ट्रस्ट से चम्पत राय का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की अपील की है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ट्रस्ट की छह जुलाई को अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें उनके इस्तीफे पर विचार हो सकता है।

बैठक से पहले संतों ने चंपत राय का समर्थन करते हुए उनका बचाव किया है। शनिवार को अयोध्या संत मंडल की एक बैठक हुई जिसके बाद संतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संतों ने कहा कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट आने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने की अपील की।

महंत राघवेश दास दास वेदांती ने कहा कि दान

राशि में गड़बड़ी के आरोपों की सच्चाई एसआईटी जांच के बाद ही सामने आएगी। उन्होंने मांग की कि ट्रस्ट से चंपत राय का इस्तीफा मंजूर न किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे आगे आकर आय-व्यय का पूरा डेबिट-क्रेडिट सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि यदि लोगों के मन में सवाल हैं तो उनका जवाब भी ट्रस्ट की ओर से दिया जाना चाहिए।

वेदांती ने कहा कि चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण में वर्षों तक मेहनत की है। वह 1993 से अयोध्या में हैं। तब से चंपत राय को काम करते हुए देख रहे हैं। उनका कहना था कि जिन लोगों ने स्वयं निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी की मांग की है, उन्हें बिना जांच पूरी हुए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और आगे का फैसला होना चाहिए। संतों ने रामभक्तों से भी अपील की कि वे अफवाहों से बचें और जांच पूरी होने तक धैर्य रखें। संतों ने एक स्वर में कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर के दान प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं है। संतों ने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का वर्षों से राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

पत्रकार वार्ता में वामनजी मंदिर, स्वर्गद्वार महंत वैदेहीवल्लभ शरण, हिन्दू धाम के महंत राघवेशदास वेदांती, विद्या कुण्ड आश्रम महामंडलेश्वर प्रेमशंकरदास, राम कचहरी महंत शशिकान्त दास, साकेत भवन महंत सीतारामदास, सदुरु बधाई भवन महंत राजीवलोचनशरण, किरार मंदिर महन्त हरिमोहनशरण, स्वामी दिव्यानंद शास्त्री, हरिमोहन शरण, महंत रवि शंकर शरण प्रमुख रुप से उपस्थित रहे।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़े लोगों को बचाया जा रहा, सरकार जवाब दे : कांग्रेस

एजेंसी, नई दिल्ली

कांग्रेस ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये के इस कथित घोटाले में केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि जिम्मेदार बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि राम मंदिर में हुई कथित चढ़ावा चोरी ने देशभर के रामभक्तों की भावनाओं को आहत किया है। इस मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों की भूमिका पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सरकार की देखरेख

में गठित ट्रस्ट के माध्यम से हुआ था। ऐसे में केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई है। आराधना मिश्रा ने कहा कि जिन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी नियुक्ति ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से एजेंसी द्वारा की गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया और पृष्ठभूमि की जांच से जुड़े सवालों पर भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि करोड़ों के चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी एजेंसियों की कोई सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। मामले की जांच केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले राम मंदिर से जुड़े भूमि सौदों को लेकर भी सवाल उठे थे। अब दान की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद देश के लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं पैदा हुई हैं। सरकार को इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। आराधना मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इससे जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि देश जवाब चाहता है।

मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, उग्रवादी तथा मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार

एजेंसी, इम्फाल

मणिपुर में सुरक्षा बलों और पुलिस ने बीते 24 घंटे में चलाए गए अलग-अलग अभियानों में कई सक्रिय उग्रवादियों तथा मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन अभियानों के दौरान हथियार, गोला-बारूद, भारी मात्रा में नकदी और संदिग्ध ब्राउन शुगर भी बरामद की गई।

मणिपुर पुलिस ने शनिवार को आधिकारिक रूप से बताया कि, शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने थौबल जिले के लांगाथेल खोंगजोम रोड क्षेत्र से केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के सक्रिय सदस्य कंगाबाम डेनी सिंह उर्फ बोनी (40) को गिरफ्तार किया।

इसी दिन आरपीएफ/पीएलए के दो सक्रिय सदस्यों को भी उनके घरों से पकड़ा गया। इनमें संगठन का एक कथित वसूलीकर्ता तथा इम्फाल वेस्ट का वित्त सचिव भी शामिल है। इनके कब्जे से दो पिस्तौल, दो बंदूकें

और बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

एक अन्य कार्रवाई में मणिपुर पुलिस ने इम्फाल ईस्ट जिले के निवासी निंगथौजाम अकंगनबा मैतेई (27) को वर्ष 2023 में एमपीटीसी पांगेई शस्त्रागार लूटकांड तथा एक रिहायशी इलाके में गोलीबारी की घटना में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया। चुराचांदपुर जिले में चलाए गए एक अन्य अभियान के दौरान पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 2.5 किलो संदिग्ध ब्राउन शुगर, 31.43 लाख नकद, एक बोलेरो वाहन तथा एक नकदी गिनने की मशीन जब्त की।

गुजरात में अति भारी बारिश का अलर्ट

एजेंसी, अहमदाबाद

गुजरात में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई है। 4 जुलाई को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक राज्य के 105 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश भावनगर जिले के महुवा में हुई, जहां मात्र दो घंटे में 3 इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 9 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 5 जुलाई को 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड शामिल हैं। इसके अलावा जूनागढ़, राजकोट, भरूच, वडोदरा, नर्मदा और छोटा उदयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि पोरबंदर,बोटाद, आनंद, पंचमहल और दाहोद के लिए येलो अलर्ट है। 6 जुलाई की चेतावनी में सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड रेड

अलर्ट और गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, भरूच और नर्मदा ऑरेंज अलर्ट तथा जूनागढ़, राजकोट, वडोदरा, छोटा उदयपुर, दाहोद और पंचमहल के लिए येलो अलर्ट है। 7 जुलाई की चेतावनी नवसारी और वलसाड रेड अलर्ट और सूरत, तापी व डांग ऑरेंज अलर्ट तथा अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, भरूच और नर्मदा येलो अलर्ट है। 8 और 9 जुलाई को नवसारी, डांग, तापी, वलसाड, अमरेली और भावनगर जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के समुद्री तट पर अगले पांच दिनों तक तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठने की संभावना है।

विधानसभा जन-आकांक्षाओं का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच, जनहित को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : ओम बिरला

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम का शनिवार को विधानसभा भवन में समापन हो गया। समापन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर. एन. रवि ने संबोधित किया। दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और संवैधानिक दायित्वों के प्रभावी निर्वहन पर जोर देते हुए जनप्रतिनिधियों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में नव-निर्वाचित एवं वर्तमान विधायकों से कहा कि विधानसभा जन-आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है। जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते

♦ पश्चिम बंगाल विधानसभा के दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का समापन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया संबोधित

हुए तथ्यों पर आधारित सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा के माध्यम से जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें। ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता जनप्रतिनिधियों की सक्रिय, जिम्मेदार और रचनात्मक भूमिका पर निर्भर करती है। प्रभावी जनप्रतिनिधित्व के लिए विधायी प्रक्रियाओं, सदन के नियमों और संसदीय परंपराओं की गहन समझ अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों की विधायी क्षमता का विकास करना और उन्हें सदन की कार्यवाही में अधिक प्रभावी एवं सार्थक भूमिका निभाने के लिए तैयार करना है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अध्ययनशील, अनुशासित और जनहित के प्रति समर्पित रहना चाहिए। सदन में प्रत्येक चर्चा और निर्णय का सीधा प्रभाव जनता के जीवन पर पड़ता है, इसलिए प्रत्येक विधायक को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल आर. एन. रवि ने भी लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और संविधान की भावना के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सफलता जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही, पारदर्शिता और संविधान के प्रति निष्ठा पर आधारित होती है। उन्होंने विधायकों से अपेक्षा की कि वे जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

04-07-2026 T.P. Page 8_Layout 1 05-07-2026 09:22 Page 1

सामंथा की 'मां इंटी बंगारम' का बनेगा सीक्वल

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'मां इंटी बंगारम' का सीक्वल बनने वाला है। इस बात की पुष्टि खुद फिल्म के राइटर राज निदिमोरू ने की है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।

'मां इंटी बंगारम' की जबरदस्त सफलता के बाद विजाग में एक ग्रैंड सक्सेस मीट रखा गया था। इसी दौरान राज निदिमोरू ने फैंस को सरप्राइज देते हुए बताया कि फिल्म का दूसरा पार्ट भी आएगा। राज ने पहले वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या वे इस कहानी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जैसे ही लोगों ने जोरदार तालियां और चीयर किया, उन्होंने सीक्वल की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, 'मेरे दिमाग में पहले से एक आइडिया है। वही टीम इस पर काम करेगी। पहली बार मुझे किसी फिल्म का दूसरा पार्ट बनाने की प्रेरणा मिली है। इसमें दोगुना मजा और दोगुना एक्साइटमेंट होगा। आगे चलकर मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा।'

राज ने यह भी बताया कि 'मां इंटी बंगारम' को लोगों से इतना प्यार मिला कि उन्हें अपने पुराने हिट प्रोजेक्ट्स से भी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि यह फिल्म सीधे दिल को छू गई। नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु के साथ गुलशन देवैया, श्रीमुखी और दिगंत मंचले नजर आए। इस फिल्म को सामंथा, राज निदिमोरू और हिमांशु ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो यह फिल्म महिला लीड पर आधारित फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

1980 के दौर पर आधारित इस कहानी में सामंथा 'स्वर्णा' का किरदार निभा रही हैं, जो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक डॉक्टर से शादी करती है। शुरुआत में उसे ससुराल वालों का प्यार नहीं मिलता, लेकिन धीरे-धीरे वह सबका दिल जीत लेती है। तभी उसका अतीत लौटकर उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मचा देता है।

सनी देओल के साथ काम करना मेरे करियर के लिए सौभाग्य की बात

अभिनेत्री दीया मिर्जा ने अभिनेता सनी देओल के साथ काम करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभिनेता के साथ काम करना, उनके करियर के लिए सौभाग्य की बात है। फिल्म 'इक्का' में दीया मिर्जा और सनी देओल साथ दिखाई देंगे। 'इक्का' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बात करते हुए दीया ने कहा कि वह हमेशा से देओल परिवार की प्रशंसक रही हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हां कहने की वजह बताते हुए दीया ने कहा, 'जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे यह बहुत दिलचस्प, मानवीय और दमदार लगी। इसमें किरदारों को बहुत अनोखे, दिलचस्प और आकर्षक ढंग से दिखाया गया है, इसलिए मुझे हां कहना ही पड़ा। सनी देओल के साथ काम करना मेरे करियर के लिए सौभाग्य की बात है और मैं इसे लेकर बहुत खुश थी।' उन्होंने अपने को-स्टार्स तिलोत्तमा शोम और अक्षय खन्ना की भी तारीफ की।

दीया मिर्जा ने कहा कि मैं हमेशा से देओल परिवार की दयालुता, उदारता और जमीन से जुड़े रहने की तारीफ करती रही हूं। सनी देओल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैंने सोचा था, बल्कि उससे भी बेहतर। मैंने टीजर लॉन्च के समय भी यह बात कही थी। ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना जिसमें तिलोत्तमा शोम और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार हों, यह सच में अद्भुत है और सिद्धार्थ ने कहानी को बहुत संवेदनशीलता और समझदारी से पेश किया है। दीया मिर्जा ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा कि अवंतिका एक ऐसी महिला है जो अपने आसपास के लोगों को अपनापन, हिम्मत और स्थिरता देती है, तब भी जब जिंदगी बहुत अनिश्चित हो जाती है। मैं उसकी हिम्मत और उस शांत साहस से प्रभावित हुई जिसके साथ वह अपनी चुनौतियों का सामना करती है।

उन्होंने कहा कि 'इक्का' की खासियत यह है कि कोर्टरूम ड्रामा के पीछे परिवार, प्यार और मुश्किल फैसलों की एक गहरी मानवीय कहानी है। मैं नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी कहानी के साथ वापसी करके बहुत खुश हूं जो भावनात्मक रूप से समृद्ध और बहुत दिलचस्प है, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे जरूर देखेंगे।

फिल्म 'मारिया' को जल्दबाजी में रिलीज करने के पक्ष में नहीं हैं रोहित शेट्टी

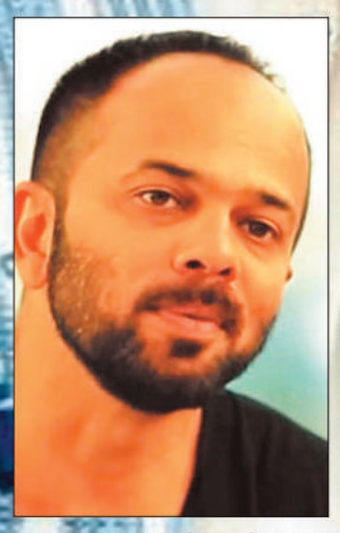

जॉन अब्राहम-तमन्ना भाटिया स्टारर प्रोजेक्ट 'मारिया' लगभग तैयार हो गया है। निर्देशक रोहित शेट्टी निर्देशित इस फिल्म में राकेश मारिया की जिंदगी और मुंबई अंडरवर्ल्ड की असली जंग पर आधारित कहानी देखने को मिलेगी। हालांकि दर्शकों को इसकी रिलीज के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आमतौर पर किसी फिल्म की 95 फीसदी शूटिंग पूरी हो जाए तो मेकर्स रिलीज डेट तलाशने लगते हैं लेकिन रोहित की इस महत्वाकांक्षी फिल्म 'मारिया' की स्थिति इसके ठीक उलट है। यह प्रोजेक्ट लगभग तैयार माना जा रहा है, बावजूद इसके इसकी बची हुई शूटिंग और रिलीज दोनों फिलहाल थमी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रोहित का पूरा ध्यान इस समय अपनी कॉमेडी फ्रेंचाइज गोलमाल पर है।

एसेल स्टूडियो से हुई थी शुरुआत, कुछ पैचवर्क का काम है बाकी

सूत्रों के अनुसार फिल्म की मुख्य शूटिंग तो काफी पहले पूरी हो चुकी है पर अभी कुछ पैचवर्क, क्लोज-अप शॉटस और सीमित सीक्वेंस ही बाकी हैं। तकनीकी तौर पर प्रोजेक्ट लगभग तैयार है लेकिन मेकर्स जल्दबाजी में इसे रिलीज करने के पक्ष में नहीं हैं। फिल्म की शुरुआत मुंबई के ट्रॉम्बे स्थित एसेल स्टूडियो से हुई थी, जहां पुलिस मुख्यालय, जांच कक्ष और प्रशासनिक दफ्तरों के बड़े सेट तैयार किए गए थे।

बॉलीवुड बनाम रीजनल सिनेमा की तुलना पर बोलीं दिव्या दत्ता

आज के दौर में बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा की तुलना करते लोग हर तरफ देखने को मिल जाएंगे। इस पर अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपने विचार रखे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को एक ही नजरिए से देखना सही नहीं है। हर जगह अच्छी और खराब दोनों तरह की फिल्में बनती हैं।

असली फर्क भाषा का नहीं, बल्कि कहानी और प्रस्तुति का होता है। जब दिव्या दत्ता से पूछा कि क्या रीजनल सिनेमा कॉमेडी फिल्मों को बॉलीवुड से बेहतर तरीके से पेश कर रहा है, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''इस तरह की तुलना करना सही नहीं है। किसी भी कॉमेडी फिल्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कहानी कितनी मजबूत है और उसे दर्शकों के सामने किस तरह पेश किया गया है। मेरा मानना है कि अगर कंटेंट अच्छा है, तो वह किसी भी भाषा में हो, दर्शकों को जरूर पसंद आता है।'' दिव्या दत्ता ने कहा, ''फिल्म इंडस्ट्री को भाषा के आधार पर बांटना ठीक नहीं है। चाहे फिल्म हिंदी में हो, किसी रीजनल भाषा में हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी हो, अगर कहानी दमदार है और उसे सही तरीके से दिखाया गया है तो वह लोगों के दिलों तक पहुंचती है। आज दर्शक काफी समझदार हो चुके हैं और वे सिर्फ नाम या भाषा देखकर फिल्म को पसंद नहीं करते, बल्कि कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं।''

सेफ हैंड में है मेरा हिंदी डेब्यू

अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म के संगीत को लेकर उत्साहित हैं जीवी प्रकाश

तमिल और तेलुगु सिनेमा में एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद जीवी प्रकाश कुमार अब 'नई नवेली' के साथ अपनी पहली बड़ी हिंदी फिल्म का म्यूजिक देने के लिए तैयार हैं। यह प्रोजेक्ट आनंद एल राय के प्रोडक्शन हाउस का है और इसे बालाजी मोहन डायरेक्ट कर रहे हैं। म्यूजिशियन जो एआर रहमान के भतीजे भी हैं ने यामी गौतम धर की फिल्म के लिए म्यूजिक बनाने, लिप-सिंक गानों के सदाबहार आकर्षण और अपनी फीस को लेकर उड़ रही अफवाहों के बारे में बात की।

अपने डेब्यू को बताया दिलचस्प

'नई नवेली' के लिए अपना पहला पूरा हिंदी म्यूजिक स्कोर तैयार करने के बारे में 'वैरायटी इंडिया' से बात करते हुए जीवी प्रकाश कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपने सफर को याद किया। प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' पर काम करने का मौका मिला, क्योंकि अनुराग कश्यप मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन यह मेरे लिए पूरी तरह से हिंदी डेब्यू नहीं था। जहां तक आनंद एल राय के बैनर तले बन रही 'नई नवेली' की बात है, तो मैं इसके सभी गाने कंपोज कर रहा हूं। यह बहुत दिलचस्प होगा। मुझे यकीन है कि गाने बहुत अच्छे बनेंगे। यामी गौतम इसमें लीड रोल निभा रही हैं। हम सब जानते हैं कि वह कितनी खूबसूरती से भावनाएं जाहिर करती हैं। इसलिए मेरे गाने सुरक्षित हाथों में हैं। 'नई नवेली', जिसे बालाजी मोहन डायरेक्ट कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म होगी जिसका बेसब्री से इंतजार रहेगा।

हर म्यूजिक स्कोर मेरे लिए एक चुनौती है

जब उनसे पूछा गया कि क्या हिंदी फिल्म के लिए म्यूजिक बनाना तमिल या तेलुगु प्रोजेक्ट पर काम करने से अलग लगता है? इस पर संगीतकार ने तुरंत किसी भी तरह के फर्क की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह तेलुगु या तमिल फिल्म से अलग नहीं है। हर म्यूजिक स्कोर मेरे लिए एक चुनौती होती है। भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर स्कोर को ऐसे बनाता हूं जैसे वह मेरा पहला स्कोर हो।

म्यूजिक कंपोजर के साथ सिंगर और एक्टर भी हैं जीवी प्रकाश

जीवी प्रकाश कुमार एक म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और एक्टर हैं। उन्होंने 120 से ज्यादा तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। उन्हें 'सूरराई पोटरु' के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का नेशनल अवॉर्ड मिला। वे मशहूर म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान के भांजे हैं। म्यूजिक के अलावा वो तमिल सिनेमा में एक लोकप्रिय एक्टर भी हैं और अपनी 2015 की फिल्म 'डार्लिंग' के लिए जाने जाते हैं।

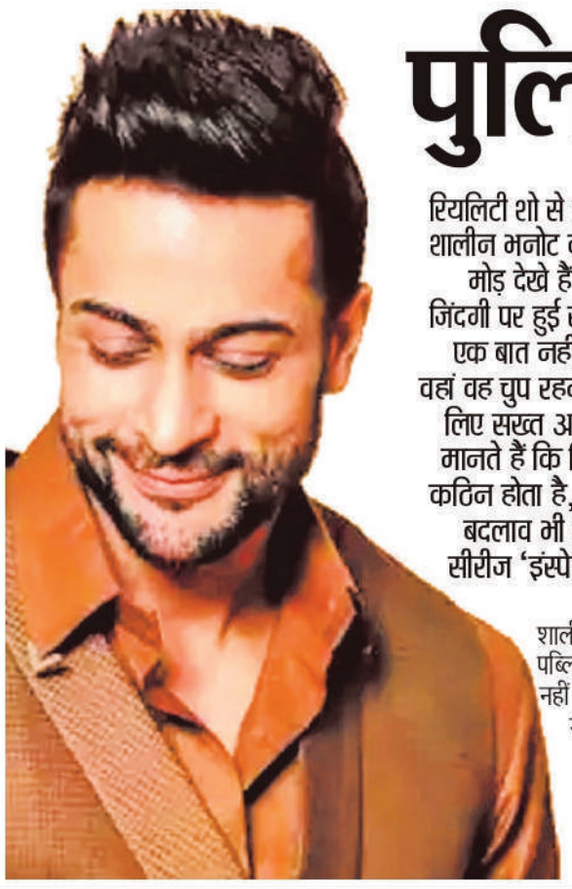

पुलिसवालों के प्रति मेरी समझ बहुत बढ़ गई

रियलिटी शो से लेकर टीवी और अब ओटीटी तक शालीन भनोट ने अपने करियर में लगातार नए मोड़ देखे हैं। उतार-चढ़ाव, चर्चाओं और निजी जिंदगी पर हुई सार्वजनिक बहसों के बीच उन्होंने एक बात नहीं बदली, जहां जरूरी नहीं होता, वहां वह चुप रहना बेहतर है। अपने किरदारों के लिए सख्त अनुशासन अपनाने वाले शालीन मानते हैं कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जितना कठिन होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण मानसिक बदलाव भी होता है। पिछले दिनों अपनी वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' के दूसरे सीजन को लेकर काफी चर्चा में रहे।

शालीन ने कहा- मेरी जिंदगी के कई फेज पब्लिक डिस्कशन में रहे पर मैंने कोई दूरी नहीं बनाई। दरअसल, मेरी पर्सनल लाइफ मेरी है। मेरा अपना एक दायरा है और मैं उसे हमेशा मेंटेन करता हूं। मैं हमेशा से ऐसा करता आया हूं। प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह है। मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने कोई दायरा बनाने के बारे में अलग से सोचा भी नहीं है। मेरी पब्लिक मेरी सब कुछ है। आज मेरे करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अलग-अलग सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर हैं, उन्हें मेरे बारे में सब पता है। मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है और मैं किसी को जज भी नहीं करता। जहां मुझे नहीं बोलना होता, वहां मैं नहीं बोलता और वैसे ही अपनी पब्लिक को भी नहीं बोलता। बाकी मेरे घर में ना मीडिया वाले घुसते और ना ही फैंस क्योंकि सबकी एक सीमा होती है। मेरे लिए फिजिकल और इमोशनल दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल हैं। अगर कोई बोले कि दो महीने के अंदर पूरा लुक बदलना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने करके देखा है इसलिए कह रहा हूं। फिजिकल के अलावा कई बार मेंटली ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। दरअसल, बोला जाता है कि यह नहीं, वो नहीं खाना है, तीन महीने बाद यह करना है। मैंने भी करीब 110 दिन बहुत डिसिप्लिन से काम किया।

पुलिसवालों के प्रति मेरी समझ बहुत बढ़ गई

एक कॉप का कैरेक्टर करने के बाद मेरी उनके प्रति समझ बहुत बढ़ गई है। कई बार हमें लगता है कि एयर होस्टेज का काम सिर्फ पानी और खाना देना है लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब दूसरी तरफ का काम समझते हैं तो पता चलता है कि वह कितना महत्वपूर्ण है। वह आपातकाल परिस्थितियों में आपकी जान बचाती हैं। उन्हें मेडिकल नॉलेज भी दी जाती है। इसी तरह, जब पुलिसवाले को देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा, यही उनका काम है लेकिन असल में उनका काम बहुत मुश्किल होता है। उसमें सही और गलत की परख करना मुश्किल है। एक पुलिसवाले के लिए, वो भी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिए यह और कठिन हो जाता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो होता है, उसे एक सेकेंड में सही और गलत का फैसला करना होता है। कहां गोली मारनी है, हवा में चलानी है, पैर पर हिट करना है, मारना है या नहीं मारना है? यह जजमेंट उसे उसी पल लेना होता है। आप जब इस बात को समझते हो तो पुलिस के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। उन्हें किसी के जीवन के बारे में फैसला लेना पड़ता है। यह बहुत मुश्किल और ट्रिकी सिचुएशन होती है।

अभी तो बहुत सारे बदलाव आने बाकी हैं

मेरा सफर रोडीज, टीवी, फिक्शन, डांस रियलिटी, बिग बॉस, बेकाबू और अब ओटीटी तक आया है। इस सफर में मैं हर फेज के बाद बदल रहा हूं। यहां तक कि जीवन के हर पल में मैं खुद को बदलता हुआ महसूस कर रहा हूं। इस साल मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सीरियसली बदल रहा हूं। हर पड़ाव में मुझे बदलाव दिखे हैं। मैंने जब बिग बॉस किया था, वह भी बहुत बड़ा पड़ाव और बदलाव था। आप जब करोड़ों लोगों के सामने एकदम से बाहर आते हो तो वह पल कमाल होता है। मैं टोरंटो में था, वहां अपना शो कर रहा था। हजारों लोग आए थे। मैंने अपने लिए स्टेडियम भरे हुए देखे हैं। मुझे लगा कि वाह क्या बात है। फिर अगले ही पल दिलजीत दोसांझ का शो देख लिया तो मन छोटा हो गया कि अभी जिंदगी में आगे बहुत कुछ पाना बाकी है। अभी तो बहुत सारे चेंजेस आने हैं और मुझे लगता है कि सारे बदलाव अच्छे ही होंगे।

टीवी जो मोहब्बत देता है, वो कोई नहीं दे सकता

टीवी और ओटीटी, दोनों मीडियम अलग हैं। टीवी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। टीवी जो मोहब्बत देता है, वो कोई नहीं दे सकता। इसके जरिए आप हर घर में पहुंच जाते हैं। आज जितना मैं जाना जाता हूं, वह टीवी की वजह से है। वही वेब की एक रिच मार्केट और ऑडियंस है।